शिक्षा बचाओ !

देश बचाओ !!

जहाँ सोच पर कोई पहरा न हो

आइसा प्रकाशन

इतिहास अलग तरीके से
घटता
अगर तुमने नहीं दिया होता
अपना अँगूठा।

पर... अँगूठा दिया तुमने,
इतिहास उनका हुआ।

एकलव्य,
तब से अब तक
उन्होंने झाँका भी नहीं तुम्हारी
ओर एक भी बार
नजरें फेर लीं।

मुझे माफ करना एकलव्य
चाशनी में डूबे उनके शब्दों
से अब नहीं बनूँगा मूर्ख
अब कभी भी नहीं कटेगा मेरा
अँगूठा।

... शशिकांत हिंगोणेकर

लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को

aisa

शिक्षा बचाओ! देश बचाओ!
जहां सोच पर पहरा न हो
आइसा की ओर से सुचेता डे और संदीप सौरभ द्वारा
यू-90 शकरपुर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित
जुलाई 2017

शिक्षा बचाओ! देश बचाओ!

जहां सोच पर कोई पहरा न हो

आइसा प्रकाशन

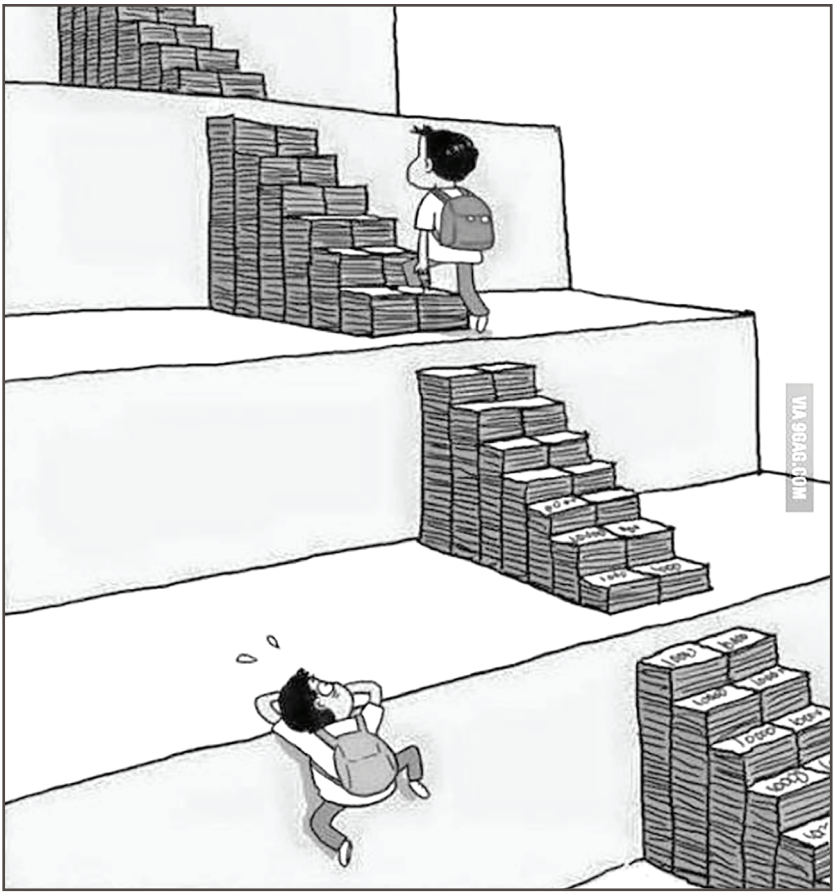
VIA 9GAG.COM

विषय-सूची

भूमिका 1

अध्याय 1:

'देशभक्ति' का कैसा पैमाना-
छात्रों के भविष्य पर हमला, कॉर्पोरेट को खजाना 5

अध्याय 2:

यूजीसी नोटिफिकेशन, 5 मई 2016:
शोध से छात्रों की बेदख़ली का फ़रमान 15

अध्याय 3:

शिक्षा में सुनियोजित भगवाकरण:
नियुक्ति, नियंत्रण, पाठ्यक्रम 20

अध्याय 4:

कैंपसों में छात्राएं और दलित: भाजपा-संघ के विचार 27

अध्याय 5:

स्कूली शिक्षा पर गहराता संकट 31

अध्याय 6:

सड़क पर स्कूल:
'जब नहीं रहेंगी परिस्थितियां अनुकूल,
तब सड़कों पर ही लगायेंगे स्कूल' 38

अध्याय 7:

बढ़ते हमले और प्रतिरोध: कैंपसों से रिपोर्ट 40

साभार: FTII छात्र आन्दोलन

भूमिका

विचारों और ज्ञान की स्वतंत्रता, देश और उसके मायने को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में यूं बयाँ किया है–

हो चित्त जहाँ भय-शून्य, माथ हो उन्नत
हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला यह जग हो
घर की संकरी भीतों से न खंडित हो दुनिया
हो जहाँ सघन सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का
हों नहीं रूढ़ियाँ रचती कोई मरुथल जिसमें
सूखे इस विवेक की धारा
हो सदा विचारों, कर्मों की गति निस्सीम की ओर
हे पिता बस उसी मुक्ति के स्वर्ग में जागे देश हमारा!

(रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि' में संकलित
'चित्तो जेथा भय शून्य' का हिन्दी अनुवाद)

शिक्षा-व्यवस्था देश के निर्माण की बुनियाद होती है। किसी देश के लोकतंत्र में वहां की आम जनता की क्या हैसियत है यह इस बात से भी निर्धारित होता है कि वहां शिक्षा लोगों को कितनी सहजता से उपलब्ध है और उसकी गुणवत्ता का स्तर क्या है। देश की तरक़्क़ी वहां के छात्रों-युवाओं के कंधों पर टिकी होती है। इसलिए, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें तर्क, विज्ञान, प्रगति और जनवाद के मूल्यों से लैस नागरिक बनाना हर राज्य की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

शिक्षा हम भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा हर बच्चे और युवा को मिले इसके लिए भारत का संविधान अपने 45वें अनुच्छेद में कहता है कि '14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को अगले 10 साल (अर्थात् 1960 तक) में शिक्षा देनी है।' इसका अनुच्छेद 14 और 15 कहता है कि बराबरी की शिक्षा दिये बग़ैर गुणवत्ता संभव नहीं है। जबकि बाज़ार का तर्क है कि शिक्षा में

गुणवत्ता सीमित लोगों के लिए ही संभव है, यानी बाजार भेदभाव पैदा करता है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं हुआ जो बराबरी की शिक्षा दिए बग़ैर शिक्षा की गुणवत्ता हासिल कर पाया हो। अब हमारी सरकारों को तय करना है कि वे देश के संविधान और यहां की जनता के प्रति वफ़ादार हैं या फिर बाज़ार की इच्छाओं प्रति! अफ़सोस कि 'देशभक्ति' के जुमलों पर इतराती सरकार ने आज हमारी संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और इसलिए हमारे देश के भविष्य के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी है।

आज सरकार की शिक्षा-नीति सचेत रूप से नागरिकों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है। 1990 के दशक में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 'दबाव' में भारत की शिक्षा-व्यवस्था को बर्बाद और बदतर करने के लिए निजीकरण की नीतियां लायी गईं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा-व्यवस्था पिछड़ी हो, सुविधायें न्यूनतम हों, पढ़ाई की गुणवत्ता निम्न दर्जे की हो- पहले इसकी तैयारियां चलीं। बाद में इसे और बदनाम करने की मुहिम चली। इस प्रकार भारत जैसे ग़रीब देश के बच्चों को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वे निजी स्कूलों की ओर दौड़ें! हाल में नीति (NITI) आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सन् 2014-15 में भारत की 3 लाख 70 हज़ार सरकारी स्कूलों (कुल सरकारी स्कूलों का 36%) में 50 से भी कम छात्रों का नामांकन है (न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 7 मई 2017)। इस तर्क से सरकारी स्कूलों को बंद करने, बेच देने और नीलाम करने की नीतियां बन रही हैं। नीति आयोग ने इस आधार पर अगले तीन साल में ऐसे स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की सिफ़ारिश की है, जिसपर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

उच्च शिक्षा को बर्बाद करने और निजी हाथों में बेचने की रफ़्तार तो और भी अधिक है। सरकारी विश्वविद्यालयों की लगातार फीसें बढ़ाई जा रही हैं। शोध और अनुसंधान (एमफिल/पीएचडी) के सारे दरवाजे बंद करने के लिए 'यूजीसी नोटिफिकेशन 2016' को जबरन कैंपसों पर थोपा जा रहा है। कैंपस लोकतंत्र और वाद-विवाद की संस्कृति पर उन्मादी हमले किए जा रहे हैं। 2016 में सरकार ने यूजीसी के फंड को 50% घटा दिया और यह सिलसिला आज भी जारी है। उच्च शिक्षण संस्थानों पर हमले चौतरफा हैं। उच्च शिक्षा के बेहतरीन संस्थानों की गुणवत्ता नष्ट कर उसे 'स्वायत्तता' के नाम पर निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है।

भाजपा और आरएसएस के वैचारिक समर्थकों और सांगठनिक व्यक्तियों को सारे नियमों को धता बताकर शैक्षणिक संस्थानों का अध्यक्ष, चेयरमैन और कुलपति

बनाया जा रहा है। साथ ही धड़ाधड़ प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें से एक भी निजी शैक्षणिक संस्थान ऐसा नहीं है जिसे (जमीन से लेकर बिजली-पानी तक में) सरकार द्वारा भारी पैमाने पर छूट न मिले हों।

मोदी सरकार के लिए देशभक्ति, विकास और युवा भारत महज़ एक जुमला है। उसका असल मक़सद कॉर्पोरेट घरानों की जी-हुजूरी और विश्व-पूंजी की चाकरी है। सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिससे भारत में उच्च शिक्षा, आधुनिक तक़्नीक और प्रगतिशील मूल्यों से लैस युवा पीढ़ी तैयार न हो, बल्कि विश्व बाज़ार के लिए सस्ते श्रमिक तैयार हों। शिक्षा, शोध, तक़्नीक और इससे उपजे अवसरों को बड़ी पूंजी के मुनाफे में झोंकने के लिए भाजपा सरकार देश के भविष्य को दांव पर लगा रही है। देश के छात्रों और युवाओं का भविष्य ही इस देश का भविष्य है। देश के युवाओं की बड़ी आबादी को या तो शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है या फिर उसे इतनी ही शिक्षा दी जा रही है कि वह 'स्किल' जुगाड़ कर कॉरपोरेट के लिए सस्ता श्रम बन जाये। कैंपस लोकतंत्र और वाद-विवाद की संस्कृति पर हमला कर वह सवाल पूछने के साहस को दबा देना चाहती है। अपनी 'स्किल इंडिया' योजना के लिए सरकार को सस्ते मजदूर तो चाहिए, लेकिन सवाल पूछने, मांग रखने वाले मज़दूर नहीं।

ऐसे समय में हमारे सामने यह चुनौती है कि हम इन हमलों की गंभीरता को समझें। नये-नये नियम व नोटिफिकेशन के जरिये, कानून के दायरे में और कानून से बाहर जाकर, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक व्यापक योजना के तहत यह कोशिश की जा रही है कि गरीबों, दलितों, वंचितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों यानी देश की अधिसंख्य आबादी को शिक्षा से वंचित कर दिया जाये। साथ ही इतिहास की धारा को पीछे मोड़ते हुए उन्हें पुराने रूढ़िवादी और सामंती संबंधों में धकेलने की भी तैयारी है. इस पुस्तिका में इन हमलों के लिए गढ़े गये 'देशभक्ति' जैसे लोकलुभावन जुमलों, इन हमलों के पीछे मौजूद कारपोरेट हितों और इन हमलों की विचारधारा, स्कूली शिक्षा की बदहाली, विभिन्न कैंपसों में छात्रों पर दमन और छात्रों द्वारा उसके प्रतिरोध की पड़ताल की गई है। यह पुस्तिका शिक्षा के क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों के बारे में कुछ तथ्य, तर्क और विचार पेश करती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह पुस्तिका देश भर के छात्र-युवा आंदोलनों व देश बचाने के संघर्ष में लगे नागरिकों को एकजुट करने में मददगार होगी और लोकतांत्रिक आंदोलनों को नया आवेग देगी। ❑

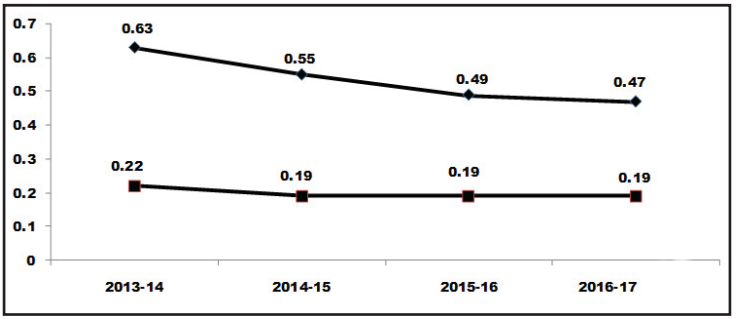

PSU banks write off Rs 1.54 lakh crore bad loans

BY PTI | UPDATED: DEC 07, 2016, 10.28 PM IST

Rs 7.4 lakh cr debt at write-off risk; keep a watch on the banks in distress

By *Amit Mudgill*, ETMarkets.com | Updated: Dec 20, 2016, 03.25 PM IST

Govt Must Bail Out Troubled Big Borrowers At Time, Says CEA Arvind Subramanian

शिक्षा पर खर्च का गिरता हुआ ग्राफ, कॉरपोरेट के लिए लाखों करोड़ों की टैक्स छूट और कर्ज माफ!

INDIA NEWS | National

अडाणी की कंपनियों को दिए कर्ज के रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी जा सकती: सीआईसी

एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Sun, 27 Nov 2016 11:55 PM IST

बाद में पढ़ें

Home › Business › Banking And Finance › Non-performing assets: Bad loan recovery by banks only gets worse in four years

Non-performing assets: Bad loan recovery by banks only gets worse in four years

According to the RBI, the rate of recovery was 18.4 per cent, or Rs 32,000 crore out of the total NPAs of Rs 173,800 crore reported in March 2014.

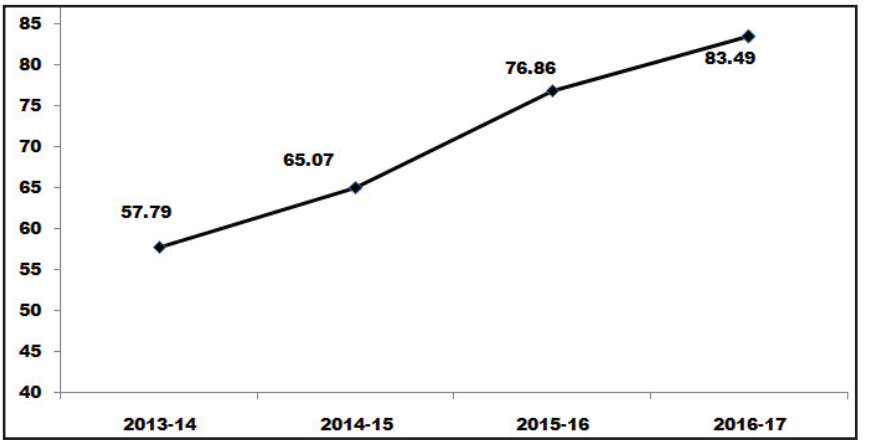

कॉरपोरेट टैक्स में छूट के कारण केन्द्रीय खजाने में हुआ नुकसान ('000 करोड़ में)

अध्याय: 1

'देशभक्ति' का कैसा पैमाना– छात्रों के भविष्य पर हमला, कॉर्पोरेट को खजाना

अब अभिव्यक्ति के सारे ख़तरे उठाने ही होंगे
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब
– मुक्तिबोध

दोस्तो! सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने देशभर के अनेक शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय और वाद-संवाद की संस्कृति का गला घोंटना शुरू कर दिया। आईआईटी चेन्नई में छात्रों के आपसी बातचीत के मंच '**अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल**' को प्रतिबंधित किया गया। **एफटीआईआई** में सिर्फ भाजपा के प्रति वफादारी की 'योग्यता' के आधार पर गजेन्द्र चौहान की नियुक्ति की गई। **हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी** में दलित शोध छात्र **रोहित वेमुला** की दु:खद सांस्थानिक हत्या में सरकार के मंत्रालय तक सक्रिय थे। **जेएनयू** के छात्रों पर पुलिसिया कहर ढाया गया, इसे बदनाम करने की कोशिशें की गईं तथा संघ व भाजपा के नेताओं ने 'शट डाउन जेएनयू' नारे के साथ इस विश्वविद्यालय को ही बंद करवाने की मुहिम छेड़ दी।

शिक्षा और छात्रों के खिलाफ भाजपा सरकार का यह रवैया आज एक संपूर्ण आकार ले चुका है। सरकारी विश्वविद्यालयों में भारी सीट-कटौती, फीस-वृद्धि और छात्रवृत्ति-बंद की सरकार की नीति ने आज सारे छात्र समुदाय के भविष्य को ख़तरे में डाल दिया है। इससे आज देश के छात्रों का भविष्य, यहां की शिक्षा का भविष्य और इसलिए हमारे देश का भविष्य पर संकट आ रहा है।

छात्रों के भविष्य पर हमला

फीस-वृद्धि और छात्रवृत्ति में कटौती: निजीकरण और शिक्षा माफियाओं से यारी, छात्रों को बाहर धकेलने की तैयारी!

अप्रैल 2017 में **पंजाब यूनिवर्सिटी** में भारी फीस-वृद्धि करने की कोशिश की गई। फीस-वृद्धि का आलम यह था कि जिस कोर्स की फीस 7,000 थी, उसे 90,000 किया गया तथा 9,000 को 1 लाख कर दिया गया है। यह तक़रीबन 1100% तक की फीस बढ़ोत्तरी है। यह सीधे-सीधे आम गरीब छात्रों को शिक्षा से बाहर धकेलने की सरकारी उद्घोषणा है। मजेदार बात यह कि इस फीस-वृद्धि का विरोध करने पर 66 छात्रों पर शुरूआत में 'देशद्रोह' का मुक़दमा भी दायर कर दिया गया। केन्द्र सरकार के अधीन आने वाली चंडीगढ़ पुलिस ने उनपर बर्बर लाठी-चार्ज किया। 58 छात्रों को जेल में डाल दिया गया। संदेश साफ है कि सरकार एक तरफ तो देश की शिक्षा-व्यवस्था को खत्म करने पर आमादा है, दूसरी तरफ वह छात्रों में भय और आतंक पैदा कर हर तरह के विरोध को दबा देना चाहती है। भाजपा सरकार 'देश' की यह कौन-सी परिभाषा गढ़ना चाहती है जहां छात्र स्वयं को शिक्षा से बेदखल किए जाने के खिलाफ भी न बोलें!

लेकिन छात्रों के जुझारू आंदोलनों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार और पुलिस के क्रूर दमन के सामने छात्रों की एकजुटता और संघर्ष ने इस भारी फीस-वृद्धि को वापस लेने पर मजबूर किया।

इसी प्रकार **इलाहाबाद यूनिवर्सिटी** की एकेडमिक काउंसिल में भारी फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया। छात्रों के तीव्र विरोध के बावजूद प्रशासन ने 200 प्रतिशत की फीस-वृद्धि छात्रों पर जबरन थोप दी। आंदोलनों के दबाव के बाद ही इसे वापस लिया गया। **लखनऊ विश्वविद्यालय** में कई विषयों में दोगुना से भी अधिक की फीस-वृद्धि की गई। वहां जिस कोर्स में फीस 16,000रु थी उसे 35,000 कर दिया गया। **टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस** में फीस को बढ़ाकर लगभग दोगुना कर दिया गया है। अप्रैल 2016 में आईआईटी के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम की फीस को बढ़ाकर 90,000रु से 2 लाख सलाना कर दिया गया। IIT मुंबई, IIT

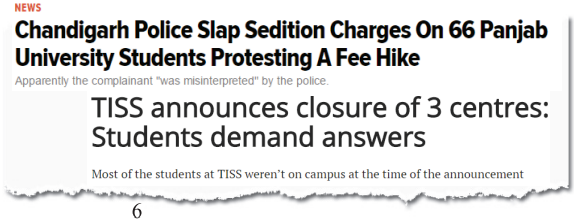
NEWS

Chandigarh Police Slap Sedition Charges On 66 Panjab University Students Protesting A Fee Hike

Apparently the complainant "was misinterpreted" by the police.

TISS announces closure of 3 centres: Students demand answers

Most of the students at TISS weren't on campus at the time of the announcement

खड़गपुर, IIT दिल्ली समेत सभी आईआईटी संस्थानों में अनेकों बार हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, परीक्षा फीस, ट्यूशन फीस आदि में बढ़ोत्तरी की गई।

2015 में यूजीसी द्वारा देश भर के शोध छात्रों के लिए **नॉन नेट फेलोशिप** को बंद करने की पुरजोर कोशिश की गई! 'ऑक्यूपाई यूजीसी' आंदोलन की देशव्यापी गूंज ने सरकार को किसी तरह पीछे धकेला। हाल में ही यूजीसी नेट की परीक्षा में 15% के बजाय 6% छात्र को ही उत्तीर्ण करने की घोषणा कर सरकार **जेआरएफ** की सीटों में भी कटौती की तैयारी कर दी है। क्योंकि नेट उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के एक छोटे हिस्से को ही 'मेरिट' अनुसार जेआरएफ दिया जाता है। **बिहार** में एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी छात्रों को उच्च शिक्षा के कई कोर्सों के लिए दी जा रही छात्रवृत्ति को 80% तक कम कर दिया गया। **प. बंगाल** के सभी विश्वविद्यालयों में अप्रैल महीने से नॉन नेट फेलोशिप को पूरी तरह से बंद कर देने की घोषणा की गई है। **टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस** ने मई 2017 में सामाजिक रूप से वंचित तबके के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कटौती कर दी गई।

दरअसल, सरकारें चाहती हैं कि शिक्षा बाजार में बिकने वाला वो सामान हो जाए, जिसकी मंडियां विदेशी पूंजी और देशी धन्नासेठों के बगीचों में सजें!

शोध से छात्रों की बेदख़ली: यूजीसी के जरिये हमला-दर-हमला

2015 में नॉन नेट फेलोशिप को ख़त्म करने की मोदी सरकार की कवायद को जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिरोध की चुनौती मिली तो सरकार ने अपना पैंतरा बदला। अब वे 5 मई 2016 के युजीसी नोटिफिकेशन के जरिये छात्रों को शोध के लिए दाखिला लेने से ही रोकने लगे। जब शोध में छात्रों को दाखिला मिलना ही बंद हो जाएगा तो फिर भला छात्रवृत्ति कैसी! अगले अध्याय में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की जायेगी।

इतना ही नहीं, 2 जून, 2017 को एक और नोटिफिकेशन द्वारा यूजीसी ने सीट कटौती का नया हमला साधा। उसने विश्वविद्यालयों को कैटेगरी में बांटकर तथाकथित

HRD ministry backs CBSE to conduct UGC-NET once a year

FIRSTPOST. 27/6/17

JNU seat cut row: Hiding under garb of 'improving' research is a systematic clampdown on higher education

कैटेगरी-3 के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी में दाख़िला के लिए नेट को अनिवार्य बना दिया। इस अनिवार्यता को थोपने के साथ ही नेट की परीक्षा को अब साल में दो बार की जगह एक बार करवाने की घोषणा की गई। साथ ही अब 15% की जगह 6% परीक्षार्थियों को ही नेट में उत्तीर्ण किया जाएगा। अर्थात् शोध में दाख़िले के लिए एक ओर नेट की अनिवार्यता तो दूसरी ओर नेट की सीटों में भारी कटौती।

सीट-कटौती के साथ-साथ विभागों को भी बंद करने की मुहिम चलाई गई। **टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस** में जेंडर स्टडीज़, सोशल एक्सक्ल्युज़न एंड इन्क्ल्यूसिव पॉलिसी तथा मानव अधिकार से संबंधित एक विभाग को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह के विभागों को चलाने के लिए अब वह पैसे नहीं देगी। हालांकि छात्रों के विरोध के कारण वहां के प्रशासन को यह कहना पड़ा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए इन विभागों को बंद नहीं किया जाएगा। (हिंदुस्तान टाइम्स, 28 मार्च 2017)

स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हाइयर एजुकेशन (2015-16) के मुताबिक उच्च शिक्षा में दाख़िला लिए कुल छात्रों में एमफिल और पीएचडी में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 0.7% और 0.4% है। ऐसे में सरकार शोध और अनुसंधान की ओर देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें और भी बाहर धकेलने का काम कर रही है।

'स्वायत्तता' के नाम पर निजीकरण

Hindustan Times7/3/17

Autonomy to DU colleges a move towards privatisation, say teachers

2 जून 2017 को प्रस्तावित रेगुलेशन द्वारा यूजीसी 'स्वायत्तता' के नाम पर बेहतर सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थाओं के निजीकरण की तैयारी में है। इस प्रस्तावित रेगुलेशन में यूजीसी देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) और नेशलन इंस्टीच्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की रैंकिंग के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटती है। कैटेगरी-1 के तहत आने वाले बेहतरीन सार्वजनिक संस्थानों को अपने संसाधन जुटाने की '**स्वायत्तता**' देने की घोषणा की गई है। मतलब साफ है कि सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर राजनीतिक नियंत्रण स्वयं रखना चाहती है और संसाधनों के मामले में उन्हें बाजार और कॉरपोरेट पर निर्भर बनाना चाहती है। यह सब '**स्वायत्तता**' के नाम पर किया जा रहा है जबकि

असली **'स्वायत्तता'** तो तब होती जब सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों पर राजनीतिक नियंत्रण न रखती और संसाधानों के लिए उन्हें बाजार पर निर्भर होने के लिए बाध्य न किया जाता। जुमलों पर टिकी इस सरकार की 'स्वायत्तता' का ब्लूप्रिंट देखिए-

- कैटेगरी-1 के कॉलेजों/संस्थानों को सेल्फ-फाइनेंस कोर्स (स्ववित्त पोषित) खोलने की पूरी आज़ादी दी गई है। इसके लिए उन्हें यूजीसी से अनुमति तक नहीं लेनी है। ऐसे विभागों और कोर्स में या तो निजी घराने पैसे लगायेंगे (निश्चित रूप से केवल कमाने के लिए) या सीधे-सीधे छात्रों को इसका खर्च देना होगा। स्पष्ट है कि जनता के गाढ़ी कमाई और पीढ़ियों के अकादमिक योगदान से निर्मित बेहतरीन संस्थानों को 'सेल्फ फाइनेंस' कोर्स के नाम पर निजी मुनाफे के लिए खोल कर उनकी विशेषताओं और चरित्र को नष्ट किया जा रहा है।

- अतिरिक्त कोर्स (रेगुलर और डिस्टेंस), रिसर्च पार्क, यूनिवर्सिटी सोसायटी से संबद्ध केन्द्र आदि शुरू करने की खुली छूट दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से पैसे नहीं दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है इसके लिए संस्थानों को अपने कैंपस परिसर, पाठ्यक्रम और प्रोजेक्ट को निजी हाथों में सौंपकर तथा छात्रों की फीस बढ़ाकर पैसे जुगाड़ना होगा।

- इस कैटेगरी के संस्थानों को यूजीसी के निरीक्षण और जांच से बाहर रखा गया है। यहां तक कि ऐसे सार्वजनिक कॉलेज/ विश्वविद्यालयों को विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के 'सहयोग' से भी चलाने की छूट दी गई है। ऐसे संस्थानों के प्रदर्शन और मूल्यांकन स्वयं उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर ही किया जाएगा। देश के बेहतरीन संस्थानों की गुणवत्ता और उनके समावेशी चरित्र को नष्ट करके उसे निजी हाथों में मुनाफे के लिए सौंपने के लिए सरकार की जल्दीबाजी देखिये!

- कैटेगरी-1 के संस्थानों को यह अधिकार और सुझाव दिया गया है कि वे सरकार द्वारा अध्यापकों के लिए निर्धारित मानदेय से अधिक की राशि देकर किसी अन्य संस्थान से 'टैलेंटेड' अध्यापकों को अपने यहां आमंत्रित करें। लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पैसा विश्वविद्यालय को छात्रों की जेब से ही लेना होगा, सरकार नहीं देगी। इस प्रकार 'अच्छे' शिक्षकों से पढ़ने का अधिकार उन्हीं को होगा जो मोटी फीस दे पायेंगे। यह प्रावधान दरअसल संस्थानों को 'अध्यापक-मंडी' में बदल देने तथा 'मार्केट-फ्रेंडली' कोर्स की भरमार लगा देने का है।

अपने इस ब्लूप्रिंट को लागू करने के लिए सरकार ने पहले से ही भाजपा-संघ विचारकों और अपने सांगठनिक दायरे के लोगों को वीसी, अध्यक्ष, चेयरपर्सन जैसे पदों पर बिठा दिया है। एक तरफ सरकार संस्थानों में नियुक्तियों और उसके

संचालन से लेकर उसके पाठ्यक्रम तक को अपनी राजनीति के तहत बदल रही है तो दूसरी ओर संसाधनों के लिए उसे निजी हाथों में सौंप रही है। विडंबना है कि इसे 'स्वायत्तता' का नाम दिया जा रहा है।

विज्ञान के क्षेत्र में भी शोध पर मार: CSIR, IIT, कोई सुरक्षित नहीं !

जून 2015 में ही सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने CSIR, IIT जैसी अनेक संस्थाओं को यह निर्देश दिया कि शोध करने वाले लैब से यह सुनिश्चित कराओ कि वे अपना फंड खुद से जेनरेट करे। इसके लिए संस्थानों के शोध के अवसरों और जरूरतों में भारी कटौती की जा रही है। छात्रों को भारी फीस चुकाने को बाध्य किया जा रहा है। शोध विषयों और स्वयं संस्थान के संचालन को निजी

भारत की उच्च शिक्षा: आंकड़ों के आइने में

निम्न नामांकन दर और वंचित तबकों की बेदख़ली

✓ हमारे देश में 18-23 साल की उम्र वाले हर 100 में महज 24.5 युवाओं को ही उच्च शिक्षा में जाने का अवसर मिलता है। जबकि उच्च शिक्षा में नामांकन में विश्व का औसत दर 34.4 है। भारत इस मामले में केवल विश्व के इस औसत दर से ही नहीं, बल्कि अल्जीरिया (34.6%) जैसे ग़रीब देश से भी पीछे है। उच्च शिक्षा में नामांकन के लिहाज से हम आज भी ब्राजील (46.4%), चिली (86.6%), अर्जेन्टीना (82.9%) और थाइलैण्ड (52.5%) जैसे देशों से काफी पीछे हैं। दुनिया के विकसित देशों में यह दर इस प्रकार है- अमेरिका- 86.7%, फ्रांस- 64.4%, ब्रिटेन- 65.5%। (स्रोत: यूनेस्को रिपोर्ट, data.uis.unesco.org)

✓ उच्च शिक्षा में नामांकन दर की स्थिति भारत के वंचित तबकों में और भी खराब है। अनुसूचित जातियों में यह दर 19.9% है जबकि आदिवासियों में सिर्फ 14.2% लोग ही उच्च शिक्षा तक जा पाते हैं।

✓ उच्च शिक्षा में नामांकन करवाने वाले कुल छात्रों में आदिवासी और मुस्लिम छात्रों की संख्या क्रमश: 4.9% और 4.7% है जबकि देश में इनकी आबादी कुल जनसंख्या का क्रमश: 8.6% और 14.2% है।

✓ पीएचडी में नामांकन करवाने वाले लोगों में महिला छात्राओं की संख्या सिर्फ़ 41% है, पुरूष छात्र 59% हैं।

✓ उच्च शिक्षा में कुल शिक्षकों में 61% पुरूष और 39% महिलायें हैं। इनमें एससी, एसटी और मुस्लिम शिक्षकों की संख्या क्रमश: 7.5%, 2.1% और 3.4% है।

पूंजी के लिए मुनाफादायी चारागाह बनाया जा रहा है। नेशनल न्युट्रिशनल मॉनिटरिंग ब्यूरो (NNMB) को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बंद करने का आदेश जारी किया है। CSIR ने बजट की कमी बताते हुए शोधार्थियों की 'ट्रैवेल ग्रांट' पर पाबंदी लगा रखी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अपने रिसर्च फंड में 15% की कटौती की है। (तीनों खबरों के लिए देखें, हिंदू, 28 अक्टूबर 2015)

संस्थानों में शोध कार्यक्रमों का नितांत अभाव

- भारत में सिर्फ़ 1.7% कॉलेज ही हैं जो कि पीएचडी प्रोग्राम चलाते हैं; सिर्फ़ 33% कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (मास्टर्स) की पढ़ाई होती है।
- उच्च शिक्षा में दाख़िला लिए कुल छात्रों में 79.3% छात्र स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर के कोर्स में हैं, 11.3% छात्र स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) स्तर के कोर्स में हैं। एमफिल और पीएचडी में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 0.7% और 0.4% है।
- विज्ञान के विषयों से स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों में सिर्फ़ 6.5% छात्र ही पीएचडी का विकल्प चुन पाते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर करने वाले कुल छात्रों में केवल 2.3% छात्र ही पीएचडी में दाखिला ले पाते हैं।

निजी कंपनियों के शिकंजे में उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा में कुल 78% कॉलेज निजी मालिकों द्वारा संचालित हैं।
- एकल कोर्स वाले 76% संस्थानों (जैसे बीएड, टिचर्स ट्रेनिंग, नर्सिंग ट्रेनिंग) को प्राइवेट सेक्टर चलाती है।
- देश के कुल 754 विश्वविद्यालयों में से 277 विश्वविद्यालय (अर्थात् 37%) निजी हाथों में हैं।

(ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित)

जून, 2017 में CSIR ने यह आधिकारिक घोषणा कर दी कि देश का यह सबसे बड़ा शोध संस्थान 'वित्तीय आपातकाल' में जा चुका है। संस्थान के पास अब किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, दूसरी ओर सरकार ने अब पैसा देने से साफ इंकार कर रखा है।

जाहिर है कि सरकार अपनी नीतियों से विज्ञान में बुनियादी शोध कार्य को भी बाधित कर रही है। सरकार विज्ञान जगत के शोध और अनुसंधान के वर्तमान ढांचे को एक तरफ निजीकरण की ओर धकेल रही है तो दूसरी ओर उसे बंद करने के विश्व बैंक के आदेश का पालन कर रही है। ऐसे में वह देश के विकास और स्वावलंबन की उम्मीदों को बड़ी पूंजी के सामने गिरवी रख रही है।

शिक्षा ओर रोजगार की तबाही भला कैसी देशभक्ति है?

आख़िर क्या वजह है, कि देशभक्ति पर अपनी छाती ठोंकने वाली और दूसरों को 'देशभक्ति' व 'देशद्रोही' का सर्टिफिकेट देने वाली यह सरकार अपने ही देश के छात्र-युवाओं को तबाह करने पर तुली है। दरअसल, ग्लोबल कैपिटल यही चाहता है कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था और शोध-संस्थान तबाह हो जायें। उन्नत देश शोध करें, और भारत जैसा विकासशील देश उनका ख़रीददार और शिकार बने। वे हमारे सपनों में सेंध मारें और हम उनके लिए सस्ते श्रम की फौज में तब्दील हो जाएं। एम.ए पूरा कर लेने के बाद अगर एम.फिल/पीएच.डी में नामांकन का रास्ता अनिश्चित या बंद रहेगा और नेट-जेआरएफ करने का रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा; तो फिर एम.ए भी क्यों? इस प्रकार छात्रों को एम.ए में दाखिला लेने से भी हतोत्साहित किया जा रहा है। राजनीति स्पष्ट है- इस सरकार को उच्च शिक्षा से लैस युवा पीढ़ी नहीं बल्कि विश्व पूंजी के लिए सस्ते श्रम की फौज तैयार करना है। हमें बीजेपी-एबीवीपी से पूछना चाहिए कि यह कैसी देशभक्ति है जहां देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है।

देश की स्वतंत्रता और उसके आत्मनिर्भर विकास की बुनियाद- शिक्षा व शोध को कॉरपोरेट मुनाफाखोरी के हवाले करना कौन-सी 'देशभक्ति' है? शिक्षा को लेकर मोदी सरकार की प्राथमिकता देखिये-

- 2013-14 में शिक्षा पर कुल केन्द्रीय बजट का 4.57% खर्च को 2016-17 में घटाकर 3.65% कर दिया गया।

• 2013–14 के केन्द्रीय बजट में शिक्षा पर खर्च कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 0.63% था, जिसे 2016–17 में घटाकर 0.47% कर दिया गया।

तब इनकी प्राथमिकता में कौन है?

कॉर्पोरेट को खजाना

• 2016–17 में मोदी सरकार ने बड़े कॉर्पोरेट्स को 83,492 करोड़ रुपये की कर-माफी (टैक्स में छूट) की। 2013–14 में यह रकम 57,793 करोड़ थी। (स्रोत: 2013–14 और 2016–17 के केन्द्रीय बजट में 'रेवेन्यू फॉरगोन' का स्टेटमेंट)

• 'इंडिया रेटिंग्स' संस्था के मुताबिक 2016 मार्च तक बैंकों द्वारा बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए गए लोन में से 13 लाख करोड़ रुपये लगभग वापस न मिलने वाले 'बैड लोन' की श्रेणी में आ गये। (डीएनए, 13 मई 2016)

✓ जेएनयू जैसा बेहतरीन संस्थान पर सरकार प्रतिवर्ष करीब 170 करोड़ रुपये खर्च करती है। वर्ष 2016–17 में कॉर्पोरेट्स को दी गई टैक्स छूट 83,492 करोड़ रुपये है। इतने पैसे से देश में जेएनयू जैसे सस्ते और गुणवत्तामूलक 491 विश्वविद्यालय चल सकते थे। बस मामला है तो सरकार की नीतियों में प्राथमिकता का!

• मोदी शासन के दौरान इस तरह के 'बैड लोन' की वसूली में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2013–14 में यह वसूली-दर 22% थी, जो 2016–17 में गिरकर 10% हो गई। (इंडियन एक्सप्रेस, 3 जनवरी 2017)

• केवल एसबीआई ने ही पिछले साल 63 बड़े पूंजीपति डिफ़ॉल्टर्स के यहां बक़ाया 7,000 करोड़ रुपये के 'बैड लोन' को माफ़ कर दिया। (डीएनए, 6 नवंबर 2016)

• एक आरटीआई के जवाब में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि एसबीआई ने अडानी ग्रुप को कितना पैसा दिया है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। (लाइव मिन्ट, 27 नवंबर 2016)

• कॉर्पोरेट की गोद में खेलने का आलम है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम 14 मार्च 2017 को कोच्ची में अपने एक संबोधन में कहते हैं- 'सरकार को बड़े कॉर्पोरेट्स के कर्जों को माफ़

कर देना चाहिए, यही उचित है और पूंजीवाद ऐसे ही काम करता है।' (पीटीआई, 14 मार्च 2017)

- मजे की बात यह है कि यह सरकार केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा भी अपने पसंदीदा कॉर्पोरेट्स अडानी और अंबानी को जनता का पैसा भेंट चढ़ा रही है। 2015 में अपने बांग्लादेश यात्रा के दौरान मोदी ने बांग्लादेश को 2 बिलियन डॉलर कर्ज दिया। फिर अप्रैल 2017 में जब शेख़ हसीना दिल्ली आयीं तो मोदी सरकार ने बांग्लादेश को 5 बिलियन डॉलर (क़रीब 32,314 करोड़ रुपये) का ऋण दिया। चौंकिये मत, दोनों ही मौके पर अडानी और अंबानी बांग्लादेश में अपना पावर प्रोजेक्ट लगा सके इसे ध्यान में रखकर ही यह 'कर्ज़' दिया गया है। (बिज़नेस स्टैण्डर्ड, 9 अप्रैल 2017)

दोस्तों, अब यह बहुत साफ़ है कि मोदी सरकार किसके साथ खड़ी है और उसके निशाने पर कौन है। देश भर के छात्रों-नौजवानों को शिक्षा, रोज़गार और लोकतांत्रिक अधिकारों से बेदखल करने की इनकी साजिश है। दूसरी ओर 'देशभक्ति', 'गो-रक्षा', 'राममंदिर', 'हिन्दू-राष्ट्र', 'लव-जिहाद' की उन्माद, आतंक और घृणा की राजनीति की जा रही है। सांप्रदायिक और उन्मादी आधार पर समाज को बाँट दिया जा रहा है। आंकड़े साफ़-साफ़ कह रहे हैं कि नीचे-नीचे जनता के पैसे को चंद पसंदीदा पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। 'बाँटो-लूटो-राज करो' की पुरानी चाल को दोहराई जा रही है।

देश की युवा पीढ़ी के लिए उन्नत विश्वविद्यालय, शिक्षा और शोध का अवसर देश की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर विकास की बुनियाद है। आइये, शिक्षा-व्यवस्था, हमारी छात्र-युवा पीढ़ी और इस देश के भविष्य पर इस चौतरफा हमले का पर्दाफ़ाश करें और हर स्तर पर उसका विरोध करें। देशभक्ति की असली कसौटी यही है, छात्र-युवा आगे बढ़कर इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभायें। ❑

अध्याय: 2

यूजीसी नोटिफिकेशन, 5 मई 2016: शोध से छात्रों की बेदखली का फरमान

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
PART III—Section 4
PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2016/ASHADHA 14, 1938

यूजीसी नोटिफिकेशन, 5 मई 2016 को देश के सभी विश्वविद्यालयों पर थोपकर सरकार ने शोध और उच्च शिक्षा के प्रति अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है –

- जेएनयू में एमफिल/ पीएचडी की कुल 970 सीटों को घटाकर 102 कर दिया गया है। अर्थात्, 86% की सीट कटौती। इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, रशियन स्टडीज, हिन्दी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत जैसे प्रमुख केन्द्रों में एमफिल/ पीएचडी के लिए कोई सीट नहीं है।
- महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में भी इस रेगुलेशन के कारण भारी सीट-कटौती हुई है। पिछले साल वहां एम.फिल के लिए 240 सीट थी, जिसे घटाकर 67 कर दिया गया। इसी प्रकार वहां पीएच.डी की 65 सीटों को घटाकर 31 कर दिया गया।
- हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिन्दी साहित्य में एमफिल के लिए 10 सीटों को घटाकर 3 कर दिया गया। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों की यही स्थिति है।

भाजपा सरकार अपने दरबारी कुलपतियों के जरिये जेएनयू समेत अन्य संस्थानों की सभी मान्यताओं और नियमों-कानूनों की धज्जियां उड़ाकर सीट कटौती पर उतारू है।

सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है?

1. यूजीसी नोटिफिकेशन, 2016 से पहले इस सरकार ने नॉन नेट फेलोशिप को रोकने में अपनी पूरी ताक़त लगा दी थी। लेकिन, जब हमारे 'ऑक्यूपाई

यूजीसी' जैसे आंदोलनों ने उनके मंसूबों को पीछे धकेल दिया तो अब उन्होंने अपना पैंतरा बदल दिया है। अब वे छात्रों के दाखिले को ही रोक देना चाहते हैं। रिसर्च में एडमिशन ही नहीं होगा तो फिर कैसी फेलोशिप।

2. यह सरकार अपनी राजनीतिक विचारधारा से जिस प्रकार पूरे देश को मध्ययुग में धकेलना चाहती है वहाँ भला शोध का क्या काम। शोध और अनुसंधान न हों और लोग यह मानना शुरू कर दें कि हवाई जहाज का राइट बंधुओं से काफी पहले किसी द्वापर या त्रेता युग में आविष्कार हो चुका था या कि चिकित्सा जगत में प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक युग की देन नहीं है, गणेश के गर्दन पर हाथी का सर हमारे यहां पहले ही लगाया जा चुका है। – संघ, उसकी सरकार और ABVP जैसे उसके अन्य संगठन यही तो चाहते हैं। देश और यहां के लोग मध्ययुगीन और सामंती मूल्यों से दबे रहें और सरकार देश की संपदा और संभावनाओं को धन्नासेठों के हाथों नीलाम करती रहे, यह इनकी राजनीति के केन्द्र में है।

3. अपने उन्मादी 'देशभक्ति' के जुमले की आड़ में सरकार देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रही है। यूजीसी नोटिफिकेशन सरकार द्वारा विश्व-बाजार की जी-हुजूरी में बनाई गई नीति है। ग्लोबल कैपिटल यही चाहती है कि उसके मुनाफे को ध्यान में रखकर हमारे देश की उच्च शिक्षा नियंत्रित हो। ताकि भारत जैसे देश के छात्र उनके खरीददार और शिकार बनें। वे हमारे सपनों में सेंध मारें; और हम उनके लिए सस्ते श्रम की फौज में तब्दील हो जाएं।

यूजीसी नोटिफिकेशन के खिलाफ एचएचआरडी पर छात्रों का प्रदर्शन

4. यूजीसी नोटिफिकेशन, 2016 के पीछे कोई अकादमिक मंशा नहीं है बल्कि यह सरकार की राजनीतिक मुहिम का हिस्सा है. इसीलिए भाजपा सरकार इसे लागू करवाने के लिए अदालत में अपने पार्टी के वकीलों को झोंक देती है। कोर्ट में इसे बाध्यकारी बनाने के लिए दो वकील जी-जान से जुटे थे- तुषार मेहता और मोनिका अरोड़ा। तुषार मेहता मोदी-अमित शाह के ख़ासम-ख़ास हैं और गुजरात में कई विवादित मामलों इनके वकील रहे हैं। बदले में सरकार ने उन्हें देश का 'एडिशनल सॉलिसिटर जनरल' बना रखा है। मोनिका अरोड़ा 1993-94 में ABVP से डीयू छात्रसंघ (डूसू) की अध्यक्ष रही हैं, 2003 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये भाजपा की प्रत्याशी थीं। जरा सोचिये कि देश की शिक्षा-व्यवस्था को तबाह करने में भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों है। अफसोस कि इस राजनीतिक हमले की कीमत आम छात्रों और देश के शिक्षा व शोध संस्थानों को चुकानी पड़ रही है।

5. यह जुमलों और प्रपंचों पर टिकी हुई सरकार है। जुमला यहाँ भी है। इस नोटिफिकेशन के ऊपर मुलम्मा चढ़ाया गया है- शोध की गुणवत्ता बढ़ाने का। लेकिन, नतीजा है सीट-कट। 'रेगुलेशन' की मानें तो शिक्षक और शोधार्थियों का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। इसके दो रास्ते हो सकते हैं। पहला तो यह कि शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जाए; और दूसरा रास्ता, कि शोधार्थियों की संख्या कम कर दी जाए, यानी कि शोध में नामांकन को ही रोक दिया जाए। साजिश यह कि जेएनयू समेत सभी विश्वविद्यालयों को यह कहा जा रहा है कि शोध में नामांकन को रोक कर ही इसे लागू करना पड़ेगा। अर्थात्, अगले कई सालों तक शोध में नामांकन नहीं होगा।

यूजीसी नोटिफिकेशन के खिलाफ जेएनयू के छात्रों शिक्षकों का साझा मार्च

जुमला देखिए कि कहा जा रहा है गुणवत्ता; और होगा सीट कट! जेएनयू के शिक्षक तो छात्रों को पढ़ाना-शोध कराना चाहते हैं, उनकी ओर से ज़्यादा बोझ की कोई शिकायत नहीं है बल्कि वे इस सीट कटौती के खिलाफ लड़ाई में छात्रों का साथ दे रहे हैं। लेकिन सरकार को यह बात नहीं पच रही। और देखिये, वर्तमान शिक्षक-छात्र अनुपात से उपजी गुणवत्ता के आधार पर 2017 में जेएनयू को 'बेस्ट यूनिवर्सिटी' का दर्जा मिला है दूसरी तरफ वीसी-सरकार उसी अनुपात का बहाना बनाकर इस 'बेस्ट यूनिवर्सिटी' पर हमला साध रहे हैं। यह नियत का खोटापन नहीं तो और क्या है जहाँ शिक्षकों की नियुक्तियां बढ़ाकर उस अनुपात को पा लेना था वहाँ छात्रों को बाहर धकेल कर संभावनाओं के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं।

इसका दूरगामी परिणाम

♦ आज जेएनयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीटों की जो संख्या है वह सीइआई अर्थात् सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीच्यूसंस एक्ट 2006 (93वां संविधान संशोधन) के तहत निर्धारित है। अर्थात्, 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए 54% की सीट बढ़ोतरी के कानून ने शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की संख्या तय की है। क्या इसे किसी अन्य कानून के द्वारा घटाया या इसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है? हैरानी की बात ये है कि इस सवाल का जवाब न तो सरकारी वकील दे रहे हैं और ना ही जज। सरकार बस अपनी राजनीतिक ताकत का दुरूपयोग कर इसे थोपने पर आमादा है।

♦ सिद्धांत के स्तर पर भी यह नोटिफिकेशन कितना अतार्किक और शिक्षा-विरोधी है आप खुद देखिए। अगर किसी विश्वविद्यालय में पहली बार शोध की पढ़ाई शुरू होती है तथा छात्रों का नामांकन शिक्षक-शोधार्थी अनुपात के 'फॉर्मूला' के मुताबिक होता है। लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि एम.फिल 2 साल और पीएच.डी 5 साल का कोर्स है, इसलिए वहां अगले 2 साल तक एम.फिल में और अगले 5 सालों तक पीएचडी में एडमिशन तो हो ही नहीं पाएगा। अर्थात् आप किस साल अपना एम.ए पूरा करते हैं, इससे तय होगा कि आप आगे की पढ़ाई जारी रख पायेंगे या नहीं। अलग-अलग साल में अपना एम.ए पूरा कर रहे छात्रों के समान अधिकार का यह खुलेआम उल्लंघन है।

♦ यह भी देखिये कि नेट-जेआरएफ का नियम ये कहता है कि जेआरएफ होने के बाद अगले दो साल के अंदर शोध के लिए अपना नामांकन करवा लेना होगा, केवल तभी आप जेआरएफ की छात्रवृत्ति पाने के हक़दार होंगे। लेकिन

इस नये नियम से जब सारे संस्थानों में दाखिला ही नहीं होगा तब मास्टर्स के बाद नेट-जेआरएफ की तरफ जाने का औचित्य भी खत्म हो जाएगा।

♦ जब किसी भी विभाग में नामांकन के लिए सीटें अनियमित और कम (टुकड़ों में) हो जाएंगी तब आरक्षण लागू करना भी लगभग असंभव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण से आसानी से खिलवाड़ किया जाएगा।

♦ एम.ए के बाद सीट कटौती यह साफ कर देगी कि 'आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है'। एम.ए पूरा कर लेने के बाद अगर एम.फिल-पीएच.डी में नामांकन का रास्ता अनिश्चित या बंद रहेगा और नेट-जेआरएफ करने का कोई मतलब नहीं बचेगा; तो फिर एम.ए भी क्यों? इस प्रकार छात्रों को एम.ए में दाखिला लेने से भी हतोत्साहित कर दिया जाएगा। राजनीति स्पष्ट है। सरकार को उच्च शिक्षा से लैस युवा पीढ़ी नहीं बल्कि विश्व पूंजी के लिए सस्ते श्रम की फौज तैयार करना है।

♦ सरकार जिस तरह से यूजीसी नोटिफिकेशन को विश्वविद्यालयों पर थोपने के फिराक में है वह सिर्फ शोध की संभावनाओं को ही नहीं ख़त्म कर रहा है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम सामने आयेंगे। एम.फिल/ पीएच.डी और नेट/जेआरएफ अगर समाप्त होता है तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षक कहां से आयेंगे। उनके लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा। उनकी पुस्तकों को कौन तैयार करेगा। क्या और कैसे पढ़ाया जाना है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी।

♦ ये कोशिशें ग्लोबल कैपिटल का हित साधने के लिए की जा रही हैं। विश्व पूंजी यह नहीं चाहती कि विकासशील देशों में शोध और अनुसंधान हो। शोध वे करें, हम उनके खरीदार बने रहें साथ में उन्हें सस्ता श्रम मुहैया करवाते रहें। देश भर में उच्च शिक्षा को समाप्त कर सरकार यूजीसी नोटिफिकेशन के सहारे उसके इसी मंसूबे को साधने में लगी हुई है।

हम हर स्तर पर इन कोशिशों का विरोध करें और इनके असली मकसद को सामने लायें। जरूरत है कि कैंपसों में 'ज्ञान-शील-एकता' का अदृश्य लबादा ओढ़कर छात्रों और इस देश के भविष्य के साथ गद्दारी करने वालों से सवाल किए जाएं। जुमला-जुमला खेलने वाले उनके आकाओं और सरकार के खिलाफ राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष तेज किए जाने की जरूरत है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर और संसद से लेकर अदालत तक हम इन्हें अलग-थलग और मजबूर कर दें। हम इस 'नोटिफिकेशन' के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों, छात्रसंघ, शिक्षकों और प्रगतिशील नागरिकों की साझी मुहिम और एकता के लिए प्रतिबद्ध हैं। ❑

अध्याय: 3

शिक्षा में सुनियोजित भगवाकरण : नियुक्ति, नियंत्रण, पाठ्यक्रम

मार्च 2017 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने शिक्षा को लेकर अपनी 'योजना' के लिए दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया। 'ज्ञान संगम' नाम से। इसमें देश भर से 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और 31 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े तक़रीबन 750 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आरएसएस न कोई शिक्षा, कला, इतिहास आदि से जुड़ी अकादमिक संस्था है, न तो यह सरकार की कोई ईकाई है। ऐसे में इस प्रकार की कार्यशाला से वे कौन-सी 'योजना' को लागू करना-करवाना चाहते हैं? इससे पहले भी आरएसएस के एजेण्डे पर मोदी सरकार ने 'स्वच्छ भारत अभियान' को विस्तृत कर शिक्षा और संस्कृति की 'सफाई' करने की बात कही है! (टेलीग्राफ़, 8 सितंबर, 2015) उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है- शिक्षा से योग्य और महत्त्वपूर्ण शिक्षकों को 'साफ' करके उनकी जगह भाजपा-संघ के वफादारों को बैठाया जाएगा। पाठ्यक्रम से विज्ञान, तर्क, तथ्य और प्रगतिशील मूल्यों की 'सफाई' कर अंधविश्वास, मिथक और कूपमंडूकता भरी जाएगी।

दरअसल, भाजपा सरकार 'संस्कृति', धर्म और मिथकों पर आधारित अपने राजनीतिक एजेंडे को शिक्षा में ठेलने पर आमादा है। इससे एक तरफ तो वे छात्रों-युवाओं को शोध, तर्क और विज्ञान से अलग करते हैं और उन्हें अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पिछड़ेपन और तर्कहीनता की तरफ धकेलते हैं। दूसरी ओर, वे इसके माध्यम से समाज और देश में अपनी घृणा, आतंक और उन्माद की विभाजनकारी व प्रतिगामी राजनीति के लिए 'कॉमनसेंस' तैयार करते हैं। संघ द्वारा निर्मित इस कॉमनसेंस' के माध्यम से महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और अन्य वंचित तबकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। भाजपा ने तरह-तरह से शिक्षा के भगवाकरण को अपना प्रमुख एजेण्डा बनाया है।

भगवा नियुक्तियां

मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही देश भर के शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में संघ परिवार के निर्देशों पर नियुक्तियां करनी शुरू कर दी। इस दौरान संबंधित पदों पर नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं बल्कि

संघ और भाजपा के प्रति वफादारी को ही 'योग्यता' माना गया। इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ऐसी नियुक्तियां पद संभालते ही संघ की प्रतिगामी और जनविरोधी विचारों को कैंपसों पर थोपना शुरू कर देती हैं। उदाहरण के लिए नीचे बॉक्स देखिए –

नाम	पद	राजनैतिक/वैचारिक कृत्य
वाई. एस. राव	चेयरमैन, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च (IRCH)	अपने ब्लॉग में लिखा कि– ''प्राचीन जाति–व्यवस्था भारत के लिए बेहतर था।''
विश्राम जमदार	चेयरमैन, NIT नागपुर	स्मृति ईरानी को अपनी इस नौकरी के लिए चिट्ठी लिखकर बताया कि– 'मैं आरएसएस का सदस्य हूं'
गजेन्द्र चौहान	चेयरमैन, FTII	'जंगल लव', 'खुली खिड़की', 'भयानक पंजा' जैसी B ग्रेड फिल्मों में किरदार निभाया। असल टैलेंट– 'मोदी–भक्ति'।
लोकेश चंद्रा	अध्यक्ष, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन (ICCR)	एक साक्षात्कार में कहा कि –'मोदी भगवान का अवतार हैं, गांधी से महान हैं, गरीबों पर कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभाव रखते हैं।'
गिरीश त्रिपाठी	वीसी, बीएचयू	इनकी कुछ टिप्पणियां– 'सरकार तो आरएसएस की ही है', 'रात में पढ़ने वाली लड़कियां अनैतिक हैं', 'मांसाहार लड़कियों को अपवित्र कर देती हैं'
ज़फ़र युनुस सरेशवाला	कुलपति, मौलाना आज़ाद नेशलन उर्दू यूनिवर्सिटी (MANUU)	ये गुजराती व्यवसायी हैं जिनकी कंपनी पर फर्ज़ीवाड़े के कई आरोप हैं, लेकिन उन्हें यह पद दिया गया क्योंकि वे मोदी के 'मुसलमान' नीतियों के 'सलाहकार' हैं।
ब्रज बिहारी कुमार	चेयरमैन, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR)	लिखते हैं– 'मोदी ने साबित कर दिया कि वे अब तक के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं।', 'वर्तमान जाति व्यवस्था और छुआछूत अरब, तुर्क और मुगलों की देन है'।

संघ संचालित पाठ्यक्रम

• भाजपा-संघ शैक्षणिक व शोध संस्थानों में अपने अंधभक्तों को जबरन नियुक्त तो कर ही रहा है, साथ ही अपने ख़तरनाक भगवा एजेण्डे को स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से लेकर पाठ्यक्रमों पर थोप रहा है।

• गुजरात सरकार ने धार्मिक आधार पर क्षेत्रों को विभाजित कर स्कूल-ड्रेस को हरा (मुस्लिम बहुल इलाकों में) और केसरिया रंग (हिन्दू बहुल ईलाकों में) के रूप में निर्धारित किया है। (इंडियन एक्सप्रेस, 14 अप्रैल, 2015)

• मध्यप्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार ने स्कूली शिक्षा में रामायण और महाभारत को सिलेबस में शामिल करने की बात कही है। इससे पहले उन्होंने स्कूलों में सूर्य-नमस्कार को अनिवार्य करने की घोषणा की थी। (टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 जनवरी, 2016)

• 'गुजरात स्टेट स्कूल टेक्स्टबुक बोर्ड' द्वारा प्रकाशित 9वीं कक्षा की हिन्दी की पाठ्यपुस्तक में 'गुरू शिष्य संबंध' अध्याय में ईसा मसीह को 'हैवान ईसा' कहा गया है। (इंडियन एक्सप्रेस, 9 जून 2017)

• राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक में बलात्कार के आरोपी आसाराम बापू को 'महान संतों' की श्रेणी में बुद्ध, मदर टेरेसा और गुरू नानक के साथ रखा गया है। (हिन्दू, 2 अगस्त, 2015) वहीं एक अन्य पाठ्यपुस्तक में अपने 'मालिक' के साथ 'वफ़ादारी' के मामले में गृहणी से बेहतर गदहे को बताया गया है! (टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 अप्रैल, 2006)

• महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड द्वारा प्रकाशित 12वीं कक्षा की 'समाजशास्त्र' की पुस्तक में महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं- 'लड़कियों की कुरूपता और अपंगता की वजह से शादी में काफी दिक्कत आती है। ऐसे में लड़की के परिवार को अधिक दहेज देना पड जाता है।' (द वायर, 2 फरवरी, 2017)

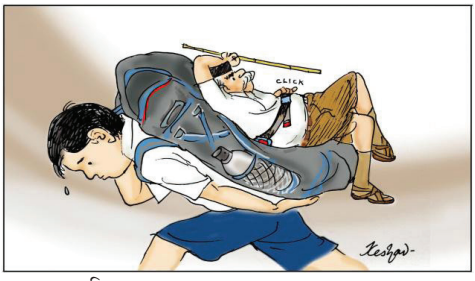

साभार: द हिन्दू

• सरकार संचालित आयुष मंत्रालय ने अपने एक बुकलेट जारी कर कहा कि 'गर्भवती महिलाओं को वासना से बचना चाहिए'। (इंडियन एक्सप्रेस, 14 जून 2017)

• आरएसएस द्वारा शिक्षा के साथ ऐसे खिलवाड़ केवल

ऊटपटांग हरकत नहीं है. संघ अपने स्कूल पाठ्यक्रमों में यह पढ़ाता है कि 'आर्य मूलत: यहीं के निवासी थे' तथा 'कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है और इसे हिन्दू शासक समुद्रगुप्त ने बनवाया था'। इतिहास में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हुई लड़ाइयां जैसे, शिवाजी-अफ़ज़ल खान, अकबर-महाराण ा प्रताप को सांप्रदायिक रंग में रंगा जा रहा है। (राम पुनियानी, sacw.net,17 फ़रवरी, 2017) जिस प्रकार अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत भारत के इतिहास का सांप्रदायीकरण किया था, भाजपा-संघ आज उसी तर्ज पर सक्रिय हैं। आज उनकी बेताबी भारत को 'हिंदू राष्ट्र' घोषित कर मुसलमानों, ईसाईयों को 'विदेशी' और 'आक्रमणकारी' घोषित करने की है।

- दीनानाथ बत्रा आरएसएस के स्कूल नेटवर्क 'विद्या भारती' के महासचिव रहे हैं तथा शिक्षा का भगवाकरण के उद्देश्य से संघ-संचालित शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के संस्थापक सदस्य हैं। उनकी पुस्तकों को भाजपा शासित गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गुजरात में इसका प्रकाशन 'गुजरात राज्य स्कूल पाठ्यपुस्तक समिति' की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लिखी भूमिका के साथ इन्हें गुजरात के 35,000 स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इन पुस्तकों के अनुसार-

➢ माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य किताब 'तेजोमय भारत' के मुताबिक विमान, प्लास्टिक सर्जरी आदि आधुनिक विज्ञान की नहीं बल्कि वेदों की देन है। हज़ारों साल पहले भारत ने 'स्टेम सेल' की खोज कर ली थी। इसका 'प्रमाण' वो महाभारत में कुंती से कर्ण और गांधारी से 100 कौरवों का जन्म के रूप में देते हैं। (इंडियन एक्सप्रेस, 27 जुलाई, 2014)

➢ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार 'अखंड भारत' के अभिन्न अंग हैं। स्कूली बच्चों को कहा जा रहा है कि वे भारत का मानचित्र इन देशों को मिलाकर 'अखंड भारत' के रूप में बनायें। (इंडियन एक्सप्रेस, 25 जुलाई, 2014)

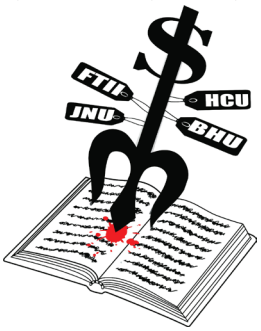

➢ अपनी एक अन्य किताब में वे लिखते हैं-'एक अंग्रेज के साथ डिनर के दौरान राधाकृष्णन ने कहा, एक दिन भगवान ने रोटी बनाई। इस दौरान उनकी पहली रोटी कच्ची रह गई और इससे अंग्रेजों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी बनाने के दौरान जल गई और इससे 'नीग्रो' का जन्म

Calling himself 'RSS person,' applicant praises Irani, weeks later is made chief of Nagpur NIT

Meet the new ICCR chief: Modi avatar of god, bigger than Gandhi

PAGE 1

SHUBHAJIT ROY
NEW DELHI, OCTOBER 31

SANGHAM

From books in schools to posts in universities, the RSS is charting out broad policy-level changes in education.

SHYAMLAL YADAV reports

Sudershan Rao's appointment as ICHR chief raises brows

Akshaya Mukul, TNN | Jul 17, 2014

Ancient caste system worked well, says the newly appointed ICHR head !

> Most worrisome was RSS affiliate being part of the discussion, says an official

ing to turn research projects into 'for-profit' ventures over the next two years."

As part of the 'Dehradun Declaration,' all laboratories signed up to "develop a revenue model in a business-like manner with a clear cost-benefit analysis.

'Indigenous science'

"The most worrisome aspect was representatives from Vigyan Bharati, an organisation affiliated to the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) being part of this discussion. The idea was to ensure 'indigenous science' was also promoted. But what was the RSS doing in this meeting," said a senior official who was a part of the meet.

बेहतरीन संस्थानों में नियुक्ति की एकमात्र योग्यता:

आर.एस.एस. के प्रति वफादारी, न कि शैक्षणिक गुणवत्ता

NEWS18 » INDIA

51 University VCs Attend RSS Workshop on Making Education More Indian

Research reality check at RSS workshop for V-Cs, teachers

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 26

AT GYAN SANGAM, the RSS's first national workshop of vice-chancellors and teachers where the outfit's chief Mohan Bhagwat was present, some-

cently worked as the all-India sah prachar pramukh, is the convener of Prajna Pravah. "It was organised to brainstorm on issues pertaining to the Bharatiya perspective of education," Nandkumar said.

The meet was to be at Hansraj College, but fearing students' protests, it was

AIIMS head to DU VC, top law officer to Medanta boss, all meet RSS chief

Bhagwat told them change can come only if govt and society work together

Indian Express25/10/14

Home › India › Dinanath Batra's moral science and verse will enter Haryana textbooks

Dinanath Batra's moral science and verse will enter Haryana textbooks

book on Hinduism.

New ICSSR chief: Caste because of invasions, Modi is best PM

RITIKA CHOPRA
NEW DELHI, MAY 8

PAGE ONE ANCHOR

Kumar succeeded Sukhdeo Thorat, who was the council's chairman since April 2011. The

Victim of intolerance

PM takes leaf from Batra book: Mahabharat genetics, Lord Ganesha surgery

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 27

SEEMING to take a page out of Dina Nath Batra's book, Prime Minister Narendra Modi has linked medical science to mythology, citing "plastic surgery" and "genetic science" to explain the creation of Lord Ganesh and Karna respectively.

Speaking at a function in Mumbai on Saturday, he said, *"Medical science ki duniya mein hum garv kar sakte hain ki hamara desh kisi samay mein kya tha. Mahabharat mein Karna ki katha, hum sab Karna ke vishay mein Mahabharat mein padhte hain. Lekin kabhi humne thod kare ki M ki Ka nahi hua ence Karn uska* can cour of ti If we hara

Gender bias being propagated in Rajasthan textbooks: Experts

शिक्षा के नाम पर तर्कविरोधी और दकियानूसी, भेदभावपूर्ण और समाज को तोड़ने वाला प्रोपेगेण्डा

Learning Sanskrit has many benefits, those who learn Sanskrit "never commits suicide ...."

Sanskrit Shikshak Sangh President D K Jha

Families pay dowry when girls are ugly: Maharashtra textbook stretches reason

An insensitive assertion made in the book, used by thousands of students over the last two years to prepare for the Higher Seconda Certificate board examinations, has drawn widespread criticism from academicians

09 JUNE 2017 Last Updated at 12:34 PM | NATIONAL

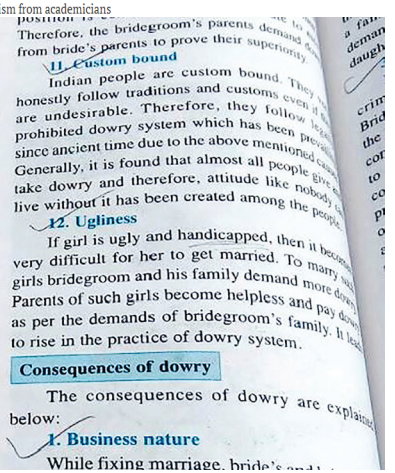

Therefore, the bridegroom's parents demand from bride's parents to prove their superiority.

11. Custom bound

Indian people are custom bound. They honestly follow traditions and customs even if are undesirable. Therefore, they follow le prohibited dowry system which has been prev since ancient time due to the above mentioned ca Generally, it is found that almost all people give take dowry and therefore, attitude like nobody live without it has been created among the people.

12. Ugliness

If girl is ugly and handicapped, then it becom very difficult for her to get married. To marry su girls bridegroom and his family demand more dowry Parents of such girls become helpless and pay dowry as per the demands of bridegroom's family. It lea to rise in the practice of dowry system.

Consequences of dowry

The consequences of dowry are explained below:

1. Business nature

While fixing marriage, bride's and

New Rajasthan Textbooks Make Way For RSS Ideologue Savarkar, Remove Nehru And Give Passing Mention to Gandhi

Many see BJP's revision of history as a way of saffronising education and glamorizing one side of the history while eliminating the other.

IndiaToday.in

New Delhi, June 12, 2017 | UPDATED 11:32 IST

Textbook blunder: Jesus Christ called 'demon' in Gujarat Class 9 book

language textbook has used the word "haivaan" (demon) before Jesus Christ instead of intended

'Good height, great complexion': Rajasthan textbook lists 'desirable traits' for entrepreneurs

एक सफल उद्यमी के गुणों की एक निश्चित सूची बनाना कठिन है। लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा बतलाये गये गुणों के आधार पर एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।

1. शारीरिक गुण – (Physical Qualities)

1. उत्तम स्वास्थ्य (Good Health)– उद्यमी का सबसे बड़ा गुण उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही उपक्रम के अन्य कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। इसके अलावा उत्तम स्वास्थ्य होने से कार्यक्षमता में वृद्धि भी हो जाती है।

2. प्रभावशाली व्यक्तित्व (Effective Personalities)- उद्यमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी अच्छी ऊँचाई, सुंदर रंग, शालीनता, गंभीरता, धीरता एवं उत्साह आदि होने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति से प्रभावी ढंग से व्यवहार एवं बातचीत की जा सके।

3. प्रसन्न मुद्रा (Cheerful looking) – उद्यमी में प्रसन्न मुद्रा का भी गुण होना चाहिए। यदि वह प्रसन्न, हँसमुख एवं तरोताजा रहता है तो अगला पक्षकार उससे प्रभावित हो जाता है।

हुआ। पहली दोनों गलतियों से सावधान होकर भगवान ने तीसरी रोटी बनाई और यह रोटी सुडौल बनी। इससे भारतीयों का जन्म हुआ।' तार्किकता और वैज्ञानिकता आधुनिक शिक्षा पद्धति का आधार है। लेकिन इसे ख़त्म कर बच्चों को पाठ्यपुस्तक में घृणा फैलाने वाली, नस्लवादी और सांप्रदायिक बातों को पढ़ाया जा रहा है।

• कोर्स में बदलाव कर के संघ अपने विचारकों को 'महान' बता कर पाठ्यक्रमों में जबरन थोप रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, भोपाल के पीजी कोर्स से नेहरू के विचारों को हटाकर आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय को डाला गया है। (हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 मार्च 2017)

• बड़ोदरा के महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी (MSU) में प्रशासन द्वारा जारी की गई डायरी और योजना कैलेण्डर में बेतुके तरीके से मिथकीय संतों को 'विज्ञान', 'परमाणु ऊर्जा' और 'रॉकेट तथा हवाई जहाज' के आविष्कारक के रूप में दिखाया गया है। (हफिंग्टन पोस्ट, 9 मार्च, 2017) इसी कॉलेज के पूर्व छात्र और विज्ञान जगत में नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकटरमण रामाकृष्णन ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि यह हरकत इस संस्थान को और पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। (इण्डियन एक्सप्रेस, 24 मार्च 2017)

• 2014 में मुम्बई में रिलायंस अस्पताल के उद्घाटन के दौरान नरेन्द्र मोदी ने शर्मनाक तरीके से यह बयान दिया कि 'जिसने हाथी के सर को गणेश में लगाया था वह निश्चित ही कोई प्लास्टिक सर्जन रहा होगा।' (इंडियन एक्सप्रेस, 28 अक्टूबर, 2014)

• लखनऊ विवि में वहां के वीसी ने 'सावरकर शोध पीठ' स्थापित करने की बात कही है, जहां सावरकर के 'मूल्यों' और 'उद्देश्यों' से संबंधित समाज निर्माण के लिए शोध किया जाएगा। (दैनिक जागरण, 29 मई 2017)

राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर हमारा संविधान कहता है कि इसका उद्देश्य हमारे देश को लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक, न्यायशील और प्रबुद्ध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाना है। भाजपा-संघ आज शैक्षणिक संस्थानों में भगवा नियुक्तियां करके, किताबें-पाठ्यक्रम को बदलकर उसमें पिछड़ी सामंती मानसिकता और इतिहास-विरोधी- विज्ञान-विरोधी बातों को डालकर शिक्षा के उसी उद्देश्य को बदल रहे हैं। ❑

अध्याय: 4

कैंपसों में छात्राएं और दलित : भाजपा-संघ का विचार

महान समाज सुधारक और आधुनिक महिला शिक्षा की नेत्री सावित्रीबाई फुले समाज और इंसान के निर्माण में शिक्षा की भूमिका के संबंध में अपनी एक कविता में लिखती हैं-

जाओ जाकर पढ़ो-लिखो
बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती
काम करो- ज्ञान और धन इकट्ठा करो
ज्ञान के बिना सब खो जाता है
ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते है
इसलिए, खाली ना बैठो, जाओ, जाकर शिक्षा लो
दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो
तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है
इसलिए सीखो और जाति के बंधान तोड़ दो ...

(सावित्रीबाई फुले की कविता-संग्रह 'काव्य-फुले' से,
शेखर पवार द्वारा मराठी से हिन्दी में अनुदित)

भाजपा नेताओं द्वारा छात्राओं का अपमान

एक तरफ जहां भाजपा सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है वहीं दूसरी तरफ उसके नेताओं द्वारा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं पर बारबार हमले हो रहे हैं। भाजपा-संघ नेताओं द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है।

- बीएचयू का वीसी स्वयं को गर्व के साथ 'संघ का आदमी' घोषित करता है। आज उस विश्वविद्यालय में इस बात की झांकी मिल जाएगी कि 'हिंदू-राष्ट्र' में महिलाओं की स्थिति क्या होगी- वहां छात्राओं को नॉनवेज खाने की अनुमति नहीं है, वे रात में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं, लाइब्रेरी में पढ़ने का उनके पास समान अधिकार नहीं है, किसी विरोध-प्रदर्शन

या राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेने के लिए उन्हें एफिडेविट जमा करना पड़ता है। (विस्तार के लिए देखिये पृ. सं. 48)

- राजस्थान से भाजपा के विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने घोषणा की कि जेएनयू की छात्रायें 'नंगी नाचती हैं' और 'प्रतिदिन 3000 कॉन्डम तथा गर्भनिरोधक सुईयां लेती हैं।[1]' दरअसल ज्ञानदेव आहूजा जेएनयू को 'अनैतिकता' के ठिकाने के रूप में पेश कर रहे हैं क्योंकि यह वो संस्थान है जहां महिलायें अपनी आज़ादी और बराबरी के लिए आवाज बुलंद करती हैं, छात्रसंघ और विभिन्न आंदोलनों को नेतृत्त्व देती हैं तथा अकादमिक-सामाजिक कामों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेती हैं।[2]
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के पूर्व 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' (ओएसडी) जवाहर यादव ने आंदोलन में भागीदारी करने वाली जेएनयू की छात्राओं को 'वेश्या से भी बदतर' कहा। (इण्डिया टूडे, 13 फरवरी 2016)
- ज्ञानदेव आहूजा और जवाहर यादव जैसे नेताओं के लिए शिक्षा और समाज में बराबरी की बात करने वाली महिलायें 'देशद्रोही' हैं क्योंकि आरएसएस के हिन्दू-राष्ट्र की अवधारणा में महिलाओं को बराबरी से वंचित रखा गया है। दलित-विरोधी और महिलाओं को सदा पिता, पति और पुत्र के अधीन मानने वाले 'मनुस्मृति' को आरएसएए भारत का संविधान बनाना चाहता है।[3]
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनुस्मृति के तर्ज़ पर अपने वेबसाइट पर लिखा कि "स्त्री को उसके बाल्यावस्था में पिता का, युवावस्था में पति का और वृद्धावस्था में पुत्र का संरक्षण मिलता है। इसलिए महिलायें आज़ाद और स्वतंत्र रहने के लिए सक्षम नहीं होतीं" योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, महिलाओं को पंचायत, असेंबली या आम चुनाव में आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए वर्ना वे 'पत्नी और मां होने की प्राथमिक जिम्मेदारियों' का वहन ठीक से नहीं कर पायेंगी।[4]
- पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और विधायक दिलीप घोष ने एबीवीपी के सदस्यों द्वारा छात्राओं को प्रताड़ित करने पर विरोध करने वाली जादवपुर यूनिवर्सिटी की छात्राओं को 'बेशर्म' कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर छात्राएं प्रताड़ित होना नहीं चाहतीं तो उन्हें आंदोलनों में शरीक नहीं होना चाहिए- ''अगर उन्हें अपने सम्मान की इतनी चिंता है तो वे वहां गई ही क्यों? यौन-प्रताड़ना का आरोप लगाना कितनी शर्मनाक और ओछी बात है।''(**TOI**, 14 मई 2016)

---

[1] http://indiatoday.intoday.in/story/in-jnu-students-dance-naked-use-3-000-condoms-and-eat-meat-says-bjp-mla/1/602799.html

[2] http://www.business-standard.com/article/pti-stories/haryana-cm-s-ex-osd-terms-jnu-students-prostitutes-116021300645_1.html

[3] http://www.indiaresists.com/rss-betrayed-india-excerpts-documents-will-shock/

[4] http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/57722872.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

• आरएसएस समर्थक और जेएनयू में प्रोफेसर मकरन्द परांजपे ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 27 अप्रैल 2017 को आयोजित एक पब्लिक मीटिंग में जेएनयू में नामांकन के दौरान पिछड़े इलाकों से आए छात्रों और महिलाओं को डिप्राइवेशन प्वांइट दिए जाने का विरोध किया। पूरे देश में जहां महिलाओं को संस्थाबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों से वंचित रखा गया है वहीं जेएनयू अपनी नामांकन पद्धति में डिप्राइवेशन प्वाइंट के चलते छात्राओं की 55% संख्या पर गर्व करता है। प्रो. परांजपे मांग करते हैं कि 'डिप्राइवेशन प्वांइट की व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए।[5]' गौरतलब है कि इस पब्लिक मीटिंग का आयोजन भी एक अन्य आरएसएस विचारक प्रकाश शाह ने किया था जो कि यूके में जातिभेद के खिलाफ कानून बनाये जाने के मुखर विरोधियों में से एक रहे हैं।

दलितों, ओबीसी और जाति-उन्मूलन के विरोध में भाजपा सरकार

नवंबर 2015 में आरएसएस के मुखपत्र 'पांचजन्य' ने जेएनयू को 'दरार का गढ़' कहा, क्योंकि उनके ही मुताबिक वहां का पाठ्क्रम और छात्र राजनीति महिलाओं और वंचित जातियों के लिए बराबरी के अधिकार को प्रोत्साहित करती है।[6] इस लेख में वामपंथियों और अंबेडकरवादियों द्वारा चलाए जा रहे तथाकथित 'जाति-संघर्ष' का विरोध किया गया है जिसके चलते वहां डिप्राइवेशन प्वाइंट लागू है तथा ओबीसी आरक्षण को सही से लागू करवाने के लिए आंदोलन चले हैं।[7]

• आरएसएस के मुखपत्र 'पांचजन्य' को पाठ्यक्रम में ''मानव अधिकार, महिला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, भेदभाव और बहिष्कार, लैंगिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता'' पढ़ाये जाने से खासी आपत्ति है। इसके मुताबिक जेएनयू में 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्ल्यूज़न', सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज़ प्रोग्राम जैसे विभाग समाज को बांटने के लिए 'लेफ्ट की साजिश' हैं। आरएसएस की दृष्टि में जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव और घृणा फैलाना 'समाज बांटना' नहीं है, लेकिन इन भेदभावों के ख़िलाफ संघर्ष करना और विचार व्यक्त करना 'समाज बांटना' है।

[5] http://www.southasiasolidarity.org/2017/05/11/professor-makarand-paranjape-audio-extract/

[6] http://panchjanya.com//Encyc/2015/11/2/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%82--%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%9D.aspx

[7] https://scroll.in/article/767556/jnu-is-no-citadel-of-divisiveness-that-label-suits-the-rss-better

• आरएसएस की इसी विचारधारा पर चलते हुए ही सरकार ने टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआईएसएस) में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूज़न एंड इंक्ल्यूसिव पॉलिसीज़, एडवांस्ड सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ और द नोडल सेंटर फॉर एक्सीलेंस अंडर द स्कीम ऑफ ह्यूमन राइट्स – तीन विभागों को बंद करने का निर्णय लिया है। बहाना है कि यूजीसी ने इन विभागों की पढ़ाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया है।[8]

• हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भाजपा के केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला जैसे अंबेडकरवादी कार्यकर्त्ता को उसके धर्मनिरपेक्ष और जाति-विरोधी विचारों के चलते 'देश-विरोधी' कहा। सरकार और उसके इशारे पर प्रशासन ने रोहित को प्रताड़ित कर उसकी सांस्थानिक हत्या तक ले गई।

• मकरंद परांजपे ने लंदन की उसी पब्लिक मीटिंग में जेएनयू में वंचित तबकों से आए छात्रों के लिए 'अतिरिक्त प्वाइंट' और आरक्षण का यह कहकर विरोध किया कि इससे विश्वविद्यालय 'अयोग्यों का जमावड़ा' हो जाएगा। स्वयं को 'हिन्दू कार्यकर्त्ता' घोषित करने वाले परांजपे अंबेडकर के 'जाति का उन्मूलन' का विरोध करते हुए कहते हैं- ''मेरा मानना है कि जाति हमारी नागरिकता और अस्मिता का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, और ऐसी चीजों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। जाति हमारी अस्मिता, अस्तित्व और पहचान है, और इसका उन्मूलन ठीक नहीं है।'' ❑

रोहित वेमुला की दलित पहचान पर 'सवाल'

साभार: आर प्रसाद

[8] http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/students-ask-for-clarity-after-tiss-announces-closure-of-three-centres/story-kRbzgaO0VeetT6SL5kuwMO.html

अध्याय: 5

स्कूली शिक्षा पर गहराता संकट

साभार: उर्दूवायर.कॉम

स्कूली शिक्षा, शिक्षा की बुनियाद है। इसलिए यह समाज-निर्माण और देश-निर्माण की प्राथमिक जरूरतों में से एक है। शिक्षा को बाजार की वस्तु बना देने पर उतारू सरकारी नीतियों ने स्कूली शिक्षा को बहुत ही भेदभावमूलक बना दिया है। आज भारत की पूरी स्कूली शिक्षा अमीरी-गरीबी में बंटी हुई है। एक तरफ जी.डी गोयनका, सिंधिया, दून स्कूल, डी.पी. एस जैसे महंगे स्कूल हैं तो दूसरी ओर बगैर पर्याप्त शिक्षक, बगैर भवन के दयनीय हाल में लाखों सरकारी स्कूल। आप खुद देखिये कि किस स्कूल में किस वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने का अवसर किनसे छीना जा रहा है? वे इस देश के मेहनतकश, गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके बच्चे वर्तमान व्यवस्था में अच्छी शिक्षा पा ही नहीं सकते। दरअसल हम एक ऐसी शिक्षा-व्यवस्था का सामना कर रहे हैं जो देश की इतनी बड़ी आबादी को अपने भीतर समाहित कर ही नहीं सकती। सरकारों की शिक्षा नीतियां मुश्किल से 10 फीसदी लोगों के लिए रही हैं।

असमानता वाली शिक्षा कभी भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकती। दुनिया में कोई भी देश इसका अपवाद नहीं है। मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा ही वह आधार है जिसपर भारत जैसा कोई देश अपनी जनता को समानतामूलक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है।

आज पूंजीपतियों की चाकरी में लगी सरकार भारत की स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर देने की साजिश रच रही हैं। हमलों का एक अनवरत दौर चल रहा है। हमारे देश की स्कूली शिक्षा किस तरह के संकटों से जूझ रही है, इसके चंद उदाहरण हैं-

• देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी स्कूलों को योजना के तहत बर्बाद किया जा रहा है। उसकी हालत को और भी बदतर बनाकर आम छात्रों को लगातार प्राइवेट स्कूलों की ओर धकेला जा रहा है। पिछले कुछ सालों से सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल और दूसरे रास्ते से निजी हाथों में देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों में जैसे होड़ मची हुई है। अब केन्द्र का नीति (NITI) आयोग ने खुद ही घोषित कर दिया कि सरकारी स्कूलों की बेहतरी उसे निजी हाथों में सौंपने में है। अपने निजीकरण के इस प्रयास को

Home > The Sunday Standard

Government schools to take private route: Niti Aayog

By Manish Anand | Published: 07th May 2017 07:52 AM |
Last Updated: 07th May 2017 01:44 PM | A+ A A- |

NEW DELHI : If India's top planning body NITI Aayog way, government school education in states and the

जायज ठहराने के लिए उन्होंने यह आंकड़ा जुटाया है कि भारत की 3 लाख 70 हजार सरकारी स्कूलों (कुल सरकारी स्कूलों का 36%) में 50 से भी कम छात्रों का नामांकन है (न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 7 मई 2017)। पहले सरकार सरकारी स्कूलों बदतर बनाकर वहां से आम छात्रों को प्राइवेट स्कूलों की ओर धकेल रही है और फिर इस नाम पर कि वहां कम छात्र हैं उन स्कूलों को निजी हाथों में सौंप रही है। इसी तरह किसी भी बहाने जनता के पैसे से बने स्कूल, उसकी ज़मीन और उसके तमाम ढांचों को निजी मुनाफ़े के लिए मुहैया करवाया जा रहा है।

• अनेक राज्य सरकारों ने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों से राज्य की शिक्षा-नीति बनाने का अनुरोध किया है। 2000 में एनडीए की सरकार ने शिक्षा के स्वरूप को तय करने के लिए 'बिड़ला-अंबानी कमिटि' बनाई थी। मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला इसके सदस्य थे। 'रिपोर्ट' में यह साफ-साफ लिखा है कि इसे चेन्नई की किसी कंपनी द्वारा लिखवाया गया।

• केन्द्र सरकारों ने समय-समय पर सूचना तकनीक की विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया कि वे शिक्षा में सूचना तकनीक की नीति बना दें।

कहानी फिनलैण्ड की-

शिक्षा को लेकर वर्ल्ड रैंकिंग में 1970 के दशक तक फिनलैण्ड की स्थिति काफी खराब थी। उसका स्थान एकदम निचले पायदान पर था। इसके उपरांत वहां एक बड़ा जनआंदोलन उभरा और लोगों ने आगे बढ़कर प्राइवेट स्कूलों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां सरकार द्वारा 'समान शिक्षा प्रणाली' लागू की गई। शिक्षा पर हो रहे पूरे खर्च को सरकार ने वहन करना शुरू किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ़्त और अनिवार्य बनाया गया। शिक्षकों का वेतन और सम्मान बढ़ाया गया। महज 30 साल में फिनलैण्ड अपने नागरिकों को शिक्षा देने में दुनिया में अव्वल स्थान पर आ गया। आज उस देश की प्रगति में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक है।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले वे छात्र जो तीसरी कक्षा के हैं और दूसरी कक्षा की पुस्तकों को पढ़ पाते हैं, केवल 19% हैं. उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे केवल 7% हैं.

(स्रोत: एनसीईआरटी और नेशनल एचिवमेंट सर्वे के आंकड़ों पर आधारित)

सरकारी स्कूलों को एक साजिश के तहत लगातार बदतर बनाया जा रहा है। सरकारों की अगंभीरता का आलम यह है कि कई बार शिक्षकों को जनगणना या चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है। पढ़ाई की गुणवत्ता और सुविधाओं के मामले में स्कूलों का स्तर लगातार गिराया जा रहा है। इसके चलते सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। 2007-08 में प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले कुल छात्र 72.6% थे। 2014 में यह घटकर 62% हो गया। कांग्रेस की उन्हीं नीतियों पर बीजेपी और भी रफ़्तार से बढ़ रही है, अभी यह संख्या और भी गिर रही है।

NEWS

90% Of Funds From 'Beti Bachao Beti Padhao' Programme Remain Unused, Says Parliamentary Panel

The report was presented by the Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development.

Extreme Neglect of Primary Education in Budget 2017

BY AMRARISH RAI ON 02/02/2017 • LEAVE A COMMENT

- प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा महंगे दाम पर खरीदने की 'वस्तु' बनाई जा रही है। हाल में इस बात पर काफी चर्चा हुई कि किस तरह से प्राइवेट स्कूलों में हर साल भारी फीस-वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं बच्चों की किताबें, कॉपियां, कई तरह के स्कूल-ड्रेस, जूते-मोजे जैसे कई सामान भी अभिभावकों को महंगी दरों पर स्कूलों से ही ख़रीदने पड़ते हैं। छोटे शहरों और कस्बाई इलाकों में कई प्राइवेट स्कूलों में 3-4 साल के बच्चे का नर्सरी या 'प्ले स्कूल' में दाखिले के लिए 20,000 से 40,000 रुपये तक देने पड़ते हैं। इन सबके बाद बच्चों की शिक्षा 'खरीदने' के लिए अलग से कोचिंग संस्थानों को पैसा देना पड़ता है।

- अपनी नीतियों से सरकार यह घोषणा कर रही है कि भारत के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के जरिये सरकार जनता के पैसे को शिक्षण संस्थान चलाने के लिए कॉपोरेट घरानों, शिक्षा माफियाओं और एनजीओ को दे रही है।

- सरकार अपनी नीतियों के जरिये देश की 80 प्रतिशत गरीब जनता को अपने बच्चे को पढ़ाने-लिखाने से हतोत्साहित कर उन्हें काम पर लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए बाल मजदूरी के कानूनों में 'बदलाव' करके 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी काम पर लगाए जाने की कानूनी छूट ले ली

साभार: *abtaknews.com*

गई है। 'बचपन में चाय बेचने' का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई 2016 में संसद द्वारा बालश्रम कानून में 'बदलाव' कर बाल मजदूरी को बढ़ावा देने का काम किया है। नये नियम के मुताबिक अब 14 से 18 साल के बच्चों को 'गैर खतरनाक' कामों में लगाया जा सकता है। दूसरी ओर इसने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 'परिवार' या 'पारिवारिक उद्यम' में काम पर लगाने की अनुमति दे दी है।

- अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मजबूरीवश महंगे स्कूलों में डालते हैं। अच्छी पढ़ाई शहर के महंगे स्कूलों में होती है, यह सोचकर ग्रामीण इलाकों से तेजी से लोग शहर की ओर विस्थापित हो रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देनी है इसकी मजबूरी में परिवार अपने समाज और अपनी खेती की जमीन से कट जाता है। बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए मध्यवर्गीय परिवारों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ रही है। अब तक पूंजीपतियों के कारखाने, बांध, नहर, एक्सप्रेस वे आदि के नाम पर तो जमीनें छीनी ही जा रही थीं। अब शिक्षा भी लोगों की खेती की जमीन बेचवा रही है!

- हमारे देश में वे बच्चे जो पहली कक्षा में दाखिला लेते हैं और 12वीं कक्षा पास करते हों, उनकी दर अत्यंत ही खराब है। सामाजिक रूप से वंचित तबकों के छात्रों का यह संकट और भी गहरा है। प्रसिद्ध शिक्षाविद अनिल सद्गोपाल ने अगस्त, 2015 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के एक सेमिनार में इस आंकड़े को रखा हैं कि आदिवासी, दलित, मुसलमान और ओबीसी के बच्चों में यह दर क्रमशः 6%, 8%, 9% और 10% है। अर्थात् अगर 100 आदिवासी बच्चों का दाखिला पहली कक्षा में होता है तो उसमें से केवल 6 छात्र ही 12वीं पास कर पाता है। 12वीं का पैमाना इसलिए कि 12वीं पास करके ही कोई शिक्षा और भविष्य से जुड़ा कोई फैसला ले पाता है! अर्थात् उन वंचित तबकों के बच्चे देश की 78% आबादी से आते हैं उनमें से 90% या उससे अधिक बच्चे तो 12वीं ही पास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उच्च शिक्षा में आरक्षण होने के बावजूद इन तबकों के बच्चों के प्रवेश का दायरा बहुत सीमित है. ऐसे में आरक्षण के

साथ-साथ हमें अपने संघर्ष का दायरा विस्तृत कर उसे इस बात से जोड़ना होगा कि वह हर बच्चा जो पहली कक्षा में दाखिला लेता है वह 12वीं पास करे।

साभार: *abtaknews.com*

- स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के नाम पर सरकार के पास कहने के लिए सिर्फ़ दो नाम है- 'केन्द्रीय विद्यालय' और 1986 की शिक्षा नीति से निर्मित 'जवाहर नवोदय विद्यालय'। देश में करीब 1125 केन्द्रीय विद्यालय हैं जबकि, नवोदय विद्यालयों की संख्या लगभग 660 है। तमिलनाडु को छोड़कर हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है। नियमानुसार इसमें हर साल छठी कक्षा में 80 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। प्रत्येक जिले में पढ़ने-लिखने की उम्र वाले छात्रों की औसत आबादी 15-20 लाख होती है। क्या इनमें से 80 छात्रों को ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए? हमारी मांग है कि देश में स्थित 14 लाख सरकारी स्कूलों को 'अपग्रेड कर' कम-से-कम केन्द्रीय विद्यालय के बराबर दर्जा और फंड दिया जाए। अगर इन 14 लाख प्राथमिक स्कूलों में पूरे शिक्षक हों, उन्हें समय पर सम्मानजनक वेतन मिले, सभी विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर हों, बेहतरीन पाठ्यक्रम हों, इसके लिए पूरा पैसा सरकार दे, तब जाकर इस देश के वे 78% बच्चे भी शायद 12वीं पास कर पायें जो आजादी के 70 साल बाद भी इससे वंचित हैं। केवल तभी एक समतामूलक समाज निर्माण की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन ताज्जुब है कि इस देश की सरकारों को 54 करोड़ की आबादी

इस संदर्भ में कोल्हापुर रियासत के राजा साहूजी महाराज (1874-1922) को याद करना प्रासंगिक है। अपने शासनकाल के दौरान साहूजी महाराज ने अपनी रियासत में केजी से पीजी तक की पूरी पढ़ाई को मुफ़्त कर दिया था। उन्होंने वंचित तबकों के सारे बच्चों-युवाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की। उनके राज्य में आदिवासी-दलित और ओबीसी छात्रों के लिए अलग से छात्रावास और स्कूल खोले गए। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी (आज का पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ जिलों को मिलाकर) में शिक्षा पर जितना खर्च करती थी उससे अधिक साहूजी महाराज अकेले कोल्हापुर में खर्च करते थे।

"सज़ा"

साभार: ब्लॉग "स्कूल्स मैटर"

''अनंत प्रतिस्पर्द्धा श्रम की भारी बर्बादी करती है और व्यक्तियों की समाजिक चेतना को अपंग बना देती है। मैं व्यक्ति की इस अपंगता को पूंजीवाद की सबसे खराब बुराई मानता हूं। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी बुराई से पीड़ित है। छात्रों में एक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिस्पर्द्धात्मक मनोवृत्ति भर दी जाती है, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजों पर काबिज होने को ही भावी कैरियर की सफलता का पैमाना मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इन बुराइयों को समाप्त करने का सिर्फ एक रास्ता है समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना और ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सामाजिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित होगी।''

– समाजवाद क्यों ? अल्बर्ट आइन्स्टाइन, 1949

वाले छात्र-युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल कर चंद अडानी-अंबानी जैसों की तिजोरी भरने की चिंता अधिक है।

देश की शिक्षा और उससे उपजे अवसरों को एक छोटे से वर्ग (उच्च वर्ग) के लिए सीमित करने की कोशिश जारी है। दूसरी ओर, विश्व बैंक चाहता है कि भारत सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे मदों पर अपना खर्च लगातार घटाये ताकि विश्व पूंजी इन क्षेत्रों से मुनाफा कमा सके। पूंजीपतियों के प्रति सरकारों की वफादारी की स्थिति यह है कि वह देश की अधिसंख्यक आबादी को संविधान से शिक्षा का अधिकार मिलने के बावजूद भी वंचित रखना चाहती है। केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्कूली शिक्षा को लेकर बनाई गई नीतियां अमीरपरस्त-अमेरिकापरस्त हैं। छात्रों, युवाओं और देश के नागरिकों को इसका विरोध करना होगा।

समान स्कूल प्रणाली (कॉमन स्कूल सिस्टम) लागू हो

अगर इस देश की पूरी जनता को सच में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी है तो उसका एक ही उपाय है- शिक्षा की बिकवाली और इसपर कब्जा बंद हो। **अर्थात् कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो!** सरकार इस बात की गारंटी करे कि देश के सभी बच्चों और युवाओं को पढ़ने-लिखने का समान अवसर मिलेगा। प्राइवेट शिक्षण संस्थान और कोचिंग को सरकार या तो अधिग्रहित करे या फिर उन्हें बंद करवाये। शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करे। हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो जाए कि वह अपने बच्चों की शिक्षा अपने घर से सबसे नजदीक के सरकारी स्कूल से ही करवाए। अर्थात् मुख्यमंत्री की संतान जिस स्कूल में पढ़े, उनके निवास के पीछे की झुग्गी के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें। हमारे और आपके इलाके के एक गरीब परिवार की संतान जिस स्कूल में पढ़े उस समाज के प्रभावशालियों की संतानें भी वहीं पढ़ें। अर्थात् **'कॉमन नेवरहुड स्कूल सिस्टम'** को लागू किया जाए। इसके माध्यम से ही जाति, धर्म, लिंग, आर्थिकी, व अन्य भेदभावों से मुक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकता है। एक समतामूलक समाज का निर्माण तभी संभव है। समान शिक्षा प्रणाली (कॉमन स्कूल सिस्टम) इस देश के संविधान में शिक्षा संबंधी चिंतन की सबसे जरूरी व्याख्या है। यह हमारे मौलिक अधिकार 'समानता का अधिकार' की मूल आत्मा है। ❑

अध्याय: 6

सड़क पर स्कूल: जब नहीं रहेंगी परिस्थितियां अनुकूल! तब सड़कों पर ही लगायेंगे स्कूल!!

बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति के खिलाफ इन दिनों भोजपुर में एक बड़ा ही रोचक और मजबूत जनप्रतिरोध खड़ा हुआ है। आंदोलन का नाम है- 'सड़क पर स्कूल'। आइसा और इंनौस (इंक़लाबी नौजवान सभा) के नेतृत्व में यह आंदोलन दिनों-दिन लोकप्रिय और मजबूत हो रहा है। एक तरफ शिक्षकों का अभाव और विकास फंड की लूट है तो दूसरी ओर पीने का पानी, 8 घंटी की पढ़ाई, कक्षाएं, शौचालय, किताब और छात्रवृत्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं। बिहार की स्कूली शिक्षा की यही स्थिति है। अधिकांश स्कूलों में पढ़ाई या तो नाममात्र की होती है या फिर सिर्फ औपचारिकताएं होकर रह जाती हैं। आजादी के 70 साल बाद भी गरीब, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे साधन-विहीन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश हैं। इस परिस्थिति के खिलाफ छात्रों-अभिभावकों और आम नागरिकों की भागीदारी से भोजपुर में सड़क पर ही स्कूल चलाने का आयोजन किया गया। इस अभूतपूर्व

आंदोलन में बच्चों की कक्षायें सड़क के बीच ही चलायी गई। इस बीच स्कूल की दयनीय स्थितियों पर भी चर्चाएं चलीं। सरकार और क्षेत्रीय अधिकारियों से अविलम्ब स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और सुविधाओं की मांग की गई।

'सड़क पर स्कूल' लगाने से पहले उस इलाके में प्रचार अभियान चलाया गया और प्रचार के अंतिम दिन शाम को उस इलाके के छात्रों व अभिभावकों के साथ मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान सारे लोग अपने बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य के लिए लड़ने का संकल्प लेते हैं। अगले दिन सड़क पर स्कूल लगाया जाता है जिसमें सबसे पहली घंटी के साथ स्कूल में प्रार्थना व राष्ट्रगान होता था फिर अगली घंटी से पढ़ाई। दोपहर में टिफ़िन में बच्चों ने नाश्ता किया और उसके बाद स्कूल में पढ़ाई फिर से शुरू होती थी। इस दौरान अधिकारियों को वहीं बुलायाा जाता और स्कूल की समस्याओं पर बात होती थी।

'सड़क पर स्कूल'
एक जनप्रतिरोध अभियान की कुछ महत्त्वपूर्ण जीत

प्रथम चरण- अगिआंव

✓ प्रथम चरण में भोजपुर के अगिआंव में मेघरियाँ गांव में आंदोलन के तीन दिन बाद ही स्कूल के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया।

✓ आंदोलन के बाद अहिले गांव के स्कूल में जाँच की टीम पहुंची। बच्चों-अभिभावकों से पूछताछ की गयी। रिपोर्ट आने पर इस मामले में और कार्रवाई होगी।

दूसरा चरण- चरपोखरी बाजार

✓ आंदोलन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने लिखित रूप में जो आश्वसन दिया था, उसे लागू करवा लिया गया। इसके मुताबिक पसौर गांव में दबंगो से उर्दू स्कूल की ज़मीन को वर्षों से कब्जा कर रखा था। उसे मुक्त करा कर भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

✓ कौआखोत गांव में स्कूल सामुदायिक भवन में चलता था। 24 मई तक गांव में ही जमीन चिन्हित कर स्कूल के लिए उपलब्ध कराया गया। इस स्कूल में अब तक एक ही शिक्षक थे, जिसे बढ़कार दो किया गया।

तीसरा चरण- नारायणपुर

✓ यहां अब स्कूल समय पर चलता है। दो घंटी के बजाय अब 5 घंटी की पढ़ाई होती है।

✓ स्कूल में एक शौचालय था लेकिन बंद रहता था ,अब उसे खोला गया। दूसरे शौचालय का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।

✓ मिड-डे मील की गुणवत्ता में सुधार लाया गया। ❑

अध्याय: 7

बढ़ते हमले और प्रतिरोध: कैंपसों से रिपोर्ट

आज मोदी सरकार द्वारा शिक्षा पर हमले की नीति ने एक सम्पूर्ण आकार लेकर देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपनी चपेट में ले लिया है। सुनियोजित तरीके से पहले सभी संस्थानों के प्रमुख ऐसे व्यक्तियों को बनाया गया है जो शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यों के प्रति नहीं, बल्कि भाजपा-संघ के शिक्षा-विरोधी, जनविरोधी एजेण्डे के प्रति वफादार हैं।

जेएनयू: सरकार, संघ और वीसी का अभियान-'शट-डाउन जेएनयू' आज भी जारी!

विश्वविद्यालय को सत्य के निरंतर और साहसिक शोध, विचारों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति और असहमतियों के प्रति सहिष्णुता के साथ खड़ा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को इन्हीं मूल्यों पर खड़े होकर छात्रों-शिक्षकों-कर्मचारियों की कई पीढ़ियों ने बनाया है। कम फीस, समावेशी (इंक्ल्यूसिव) नामांकन पद्धति, बहस-असहमतियों का सम्मान करती यहां की संस्कृति और अपने विमर्शों में जनपक्षधरता लिए ऐसे विश्वविद्यालय के उदाहरण भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया में कम मिलेंगे। आज जेएनयू की इन्हीं मूल्यों और विशेषताओं पर व्यवस्थित हमला है। वाइस चांसलर जगदीश कुमार को इसे नष्ट करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा भेजा गया है। उन्होंने 27 जनवरी 2016 को जेएनयू के वाइस चांसलर का पद संभाला। तब से इनके सिलसिलेवार हमलों पर एक नजर डालिए-

- 9 फरवरी 2016 को हुए एक कार्यक्रम को बहाना बनाकर भाजपा नेताओं ने जेएनयू को 'देशद्रोही' के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। पूरे जेएनयू समुदाय के खिलाफ जमकर 'मीडिया ट्रायल' चलाया गया। 'देशप्रेम' के उन्माद पर पूरे कैंपस को मॉब लिंचिंग की ओर धकेला जा रहा था। स्थिति यह थी कि यहां के छात्र और शिक्षक कैंपस के बाहर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। यहां तक कि एक उन्मादी भाजपाई भीड़ ने छात्रसंघ अध्यक्ष पर कोर्ट परिसर में हमला कर दिया।

दूसरी ओर, जेएनयू वीसी ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस और संघी मीडिया को कैंपस में आमंत्रित कर जेएनयू को 'देशद्रोही' करार देने की कोशिश की। उसने न सिर्फ छात्रों को गिरफ़्तार करवाया बल्कि 'हाई लेवल इन्क्वाइरी कमिटी' के नाम पर यहां के छात्र नेताओं को चुन-चुन कर निशाना बनाया।

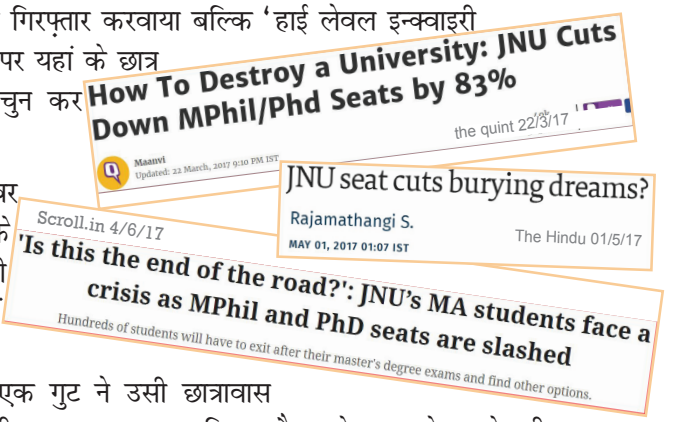

- 14 अक्टूबर को जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास में एबीवीपी के कार्यकर्त्ताओं के एक गुट ने उसी छात्रावास के एक छात्र नजीब पर हमला कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके अगले दिन से नजीब आज तक लापता है। 'नजीब को न्याय' की मांग पर दिल्ली पुलिस, भाजपा सरकार और वाइस चांसलर जगदीश कुमार का रवैया बेहद शर्मनाक है। इस पूरे मामले में जेएनयू प्रशासन ने संघ के कार्यालय और एजेण्ट होने की ही भूमिका निभाई। वीसी को यह घटना इतनी छोटी बात लगी कि उन्होंने सजा के नाम पर एवीबीपी के उन हमलावरों को 'हॉस्टल बदलने की 'सजा'(?)' दी। इस पूरे मामले में पहले तो वीसी ने 'नजीब पर हमला हुआ है' इस बात को ही हर जांच से गायब करना चाहा; जबकि स्वयं प्रशासन की 'इन्क्वाइरी कमिटि' ने एबीवीपी के उन आरोपियों को दोषी करार दिया। यहां

तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई बार इसे लेकर प्रशासन को फटकार लगायी। किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख पद पर होने के नाते क्या यह वाइस चांसलर की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने ही कैंपस में हमले के शिकार एक छात्र को न्याय की गारंटी करे। उससे भी बढ़कर उसके गायब हो जाने के बाद उसे सुरक्षित वापस लाने की गारंटी करे- कम-से-कम उसकी कोशिश ईमानदार हो।

- 11 दिसंबर की रात 11-12 बजे वीसी जगदीश कुमार के आदेश से अचानक प्रशासनिक भवन के उस हिस्से को शीशे की दीवारों और लोहे की सलाखों से 'पैक' किया जाने लगा जो अब तक छात्रों का एक प्रोटेस्ट-स्पेस था। इस हिस्से को जेएनयू के आम छात्र और छात्रसंघ भूख हड़ताल, धरना आदि के लिए दशकों से इस्तेमाल करता रहा है। यह कैंपस की प्रोटेस्ट कल्चर को खत्म कर इसे जेलखाने में बदल देने की तैयारी है।

- जेएनयू प्रशासन ने सरकारी नीतियों और प्रशासन द्वारा कैंपस पर हमलों का विरोध करने पर छात्रों को सजा, निलंबन और 'नोटिस' देने की नीति अपनाई है। इस दौरान पुरानी घटनाओं को आधार बनाकर धड़ल्ले से लेफ्ट और प्रोग्रेसिव आंदोलनों से जुड़े छात्रों और छात्रनेताओं को 'नोटिस' व सजा दी जा रही है। 'नजीब को न्याय', 'मई दिवस' 'जय-भीम' लिखने, 'मूवी स्क्रीनिंग' में भागीदारी करने जैसी बातों पर भी छात्र-नेताओं को 'सजा' सुनाई गई है।

नजीब के लिए न्याय हेतु आन्दोलन

एक बेहतरीन विश्वविद्यालय के रूप में जेएनयू ने जिन मूल्यों और नियमों को तैयार किया था, आज उसे ताक पर रखकर वीसी यहां संघ के एजेण्डे को साधने में लगा हुआ है–

✓ चेयरपर्सन नियुक्ति में वरिष्ठता के पैमाने को नकारकर संघी विचारधारा और सांगठनिक नजदीकियों को आधार बनाने की कोशिश की गयी।

✓ वार्डेन की नियुक्ति में पुराने कायदे कानूनों को दरकिनार कर उन लोगों को 'शॉर्टकट' से वार्डेन बना दिया गया जो भाजपा–एबीवीपी–आरएसएस के कैडर और समर्थक हैं!

✓ 2016 की प्रवेश परीक्षा के समय जेएनयू प्रशासन ने तमाम विभागों पर परीक्षा होने से पहले ही 'आंसर की (उत्तर)' जमा करवाने का दबाव बनाया था। हालांकि शिक्षकों ने आंसर की पहले देने से साफ मना कर दिया। इसके पीछे वीसी और प्रशासन का मकसद क्या था, आप खुद समझ सकते हैं।

✓ वाइस चांसलर ने जब नये छात्रों के लिए 'ओरिएंटेशन' प्रोग्राम किया तो उसमें जेएनयू छात्रसंघ और जीएसकैश जैसी संस्थाओं को नहीं बुलाया गया। पूरे कार्यक्रम के संचालन और व्यवस्था में एबीवीपी को रखा गया।

✓ सारे महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक और निर्णय लेने वाले पदों पर आरएसएस के विचार और संगठन से सहमति रखने वाले लोगों को बिठा दिया गया है। उनकी नियुक्तियों में नियमों–कानूनों की बिना कोई परवाह किये बगैर।

✓ आरएसएस से अलग विचारों पर प्रशासन ने जैसे पहरा बैठा दिया है। हॉस्टल मेस में पब्लिक मीटिंग को लगभग बंद कर देने की योजना चलाई जा रही है।

यूजीसी नोटिफिकेशन व सीट कट के खिलाफ प्रदर्शन

एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे मंच को वीसी ने अपने खतरनाक मंसूबों के लिए 'हाइजैक' कर इसमें सबसे प्रतिक्रियावादी, अलोकतांत्रिक और छात्र-विरोधी नीतियों को पारित किया-

➲ वाइस चांसलर ने 'यूजीसी नोटिफिकेशन, मई 2016' को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। इस नोटिफिकेशन द्वारा एमफिल/ पीएचडी की कुल 970 सीटों को घटाकर 102 कर दिया गया।

➲ फैकेल्टी नियुक्ति के लिए वीसी ने स्वयं को सर्वेसर्वा घोषित करने का प्रस्ताव भी पास किया। इसका सीधा मतलब निष्पक्ष नियुक्ति की प्रक्रिया को खत्म कर भाजपा-आरएसएस के इशारों पर भगवा नियुक्तियों को शुरू करना है।

➲ कैंपस की अकादमिक स्वायत्तता खत्म कर शिक्षा का भगवाकरण करने की सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जेएनयू में नये-नये कोर्स और विषयों को जबरदस्ती घुसाने की भरसक कोशिश चल रही है। 'वैदिक संस्कृति', 'योगदर्शन' जैसे कोर्स जिनके लिए यहां न तो कोई सांस्थानिक ढांचा मौजूद है और ना ही अकादमिक गुणवत्ता में उनका कोई योगदान है, केवल संघ के एजेण्डे पर चलकर वीसी इन्हें जबरदस्ती लागू करवाने पर तुले हैं।

➲ इसी प्रकार 3 फरवरी 2017 को हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में उन तमाम छात्र-विरोधी, जेएनयू-विरोधी प्रस्तावों को 'पास' करा लिया गया, जो एक संस्था को तबाह करने वाले थे।

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी: 'कैंपस में आपातकाल के खिलाफ संघर्ष जारी है'

- अप्रैल 2016 में विवि प्रशासन ने अपने नए प्रॉस्पेक्टस में भारी फीस-वृद्धि की घोषणा कर दी। उस वर्ष BE(Civil) जैसे कोर्स में नामांकन फीस को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 38,000 कर दिया गया। छात्रों के लगातार आंदोलन की वजह से बाद में इस कोर्स के छात्रों को 20,000 लौटाया गया।

- प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों व छात्र-नेताओं को नियमित रूप से 'नोटिस', 'कारण बताओ नोटिस', 'निलंबन' आदि के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।

- पिछले साल 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पूर्व एकबार फिर जामिया के छात्रों के बीच दहशत फैलाने की कोशिश की गई। भाजपा सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ हॉस्टल में

बिना किसी 'अनुमति' के घुस गई। छात्रों के भारी विरोध के बाद वे पीछे हटे। जामिया मिल्लिया जैसे एक अल्पसंख्यक संस्थान पर 'आतंक-विरोध' के नाम पर 'राजकीय आतंक' और 'उत्पीड़न' की घटनायें पहले भी हुई हैं। इस बार इसके खिलाफ प्रशासन-सरकार को तीव्र आंदोलन का सामना करना पड़ा। कैंपस के बाब-ए-ग़ालिब को लगातार 5 दिनों तक छात्रों ने आंदोलन का केन्द्र बना दिया। प्रशासन को 'माफीनामा' देना पड़ा तथा आगे से वे ऐसा नहीं करेंगे, यह लिखकर देना पड़ा। लेकिन इस आंदोलन ने जामिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया- कैंपस लोकतंत्र, वाद-विवाद की संस्कृति, और छात्रसंघ-चुनाव वहां की लोकप्रिय और ज्वलंत मांग बन गई। आज जामिया में पब्लिक मीटिंग, पर्चा-पोस्टर, क्लास-कैम्पेन आदि राजनीतिक-वैचारिक गतिविधियां शुरू हो गई।

- मार्च 2017 में प्रशासन ने एक बार फिर फीस-वृद्धि की कोशिश की। इसके विरोध में आंदोलन हुए और प्रशासन ने अपना निर्णय वापस ले लिया।

- छात्रसंघ चुनाव के लिए दशकों से उठायी जा रही मांग को 'सीमित' करने के उद्देश्य से प्रशासन ने 'स्टूडेंट काउंसिल' का प्रस्ताव रखा जिसमें 'सीआर' (क्लास रिप्रजेन्टेटिव) को नियुक्त और अनुमोदित किया जाएगा। यह साफ-साफ छात्रों के गंभीर और जरूरी मांग के प्रति प्रशासन की संवेदनहीनता थी। छात्रों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल वहां 'स्टूडेंट काउंसिल' के चुनाव पर रोक है।

आज जामिया में लंबे समय के बाद छात्र-आंदोलनों का उभार देखा जा रहा है। लंबे समय तक वहां के 'कैंपस लोकतंत्र' पर सरकारों ने और उनके इशारे पर प्रशासन ने ताला जड़ रखा था। इस नई सुगबुगाहट को आज देश भर में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों पर विस्तृत हमले के खिलाफ और भी बुलंद होना है।

दिल्ली विश्वविद्यालय: प्रशासन, पुलिस और सरकार के संरक्षण में संघियों की गुण्डागर्दी

77 कॉलेजों और 5 संबद्ध कॉलेजों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय अपने रेगुलर (1 लाख 32 हज़ार) और अनौपचारिक प्रोग्राम (2 लाख 61 हज़ार) से करीब 4 लाख की छात्र-आबादी को शिक्षा देने वाला सरकारी संस्थान है। सरकार इसके सार्वजनिक चरित्र को क्रमशः निजीकरण की ओर धकेल रही है। सरकार कैम्पस लोकतंत्र को एबीवीपी के हवाले कर, उसे तबाह कर तथा विभिन्न कॉलेज-कैम्पसों की स्वायत्तता और गुणवत्ता को नष्ट कर रही है। दिल्ली के आसपास

एबीवीपी की गुण्डागर्दी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय में आम छात्रों व शिक्षकों का ऐतिहासिक मार्च, 28 फरवरी 2017

कुकुरमुत्ते की तरह उग आए प्राइवेट कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को सरकार सिर्फ जमीन–बिजली–पानी देकर ही संतुष्ट नहीं है। वह अब इस 4 लाख की आबादी को भी उस 'मकड़जाल' की ओर धकेलना चाहती है। फीस बढ़ाये रखो, गुण्डागर्दी को बढ़ावा दो, शिक्षकों के पदों को रिक्त रखो, कॉर्पोरेट के इशारे पर गुणवत्ता खत्म करते जाओ– देखो, छात्र खुद ही प्राइवेट कॉलेजों की ओर भागेंगे।

- मोदी के सत्ता में आने के बाद यहां उनके छात्र संगठन एबीवीपी को दोनों ओर से संरक्षण मिलना शुरू हो गया– विवि प्रशासन से भी और पुलिस से भी। यहां एबीवीपी की गुण्डागर्दी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन उनपर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज में 'मुजफ्फरनगर बाकी है' फिल्म दिखाये जाने पर तोड़–फोड़ की। इन लोगों ने खालसा कॉलेज के एक थियेटर ग्रुप को खुलेआम धमकियां दी। हाल में नामांकन के इच्छुक छात्रों के लिए लगाए गए आइसा द्वारा लगाए गए 'सहायता डेस्क' पर ने हमले किए। छात्र–आंदोलन से जुड़े कार्यकर्त्ताओं पर इनके हमले की कई घटनायें आये दिन सामने आ रही हैं।

- भाजपा और संघ की विचारधारा से अलग किसी अन्य विचारों से जुड़े कार्यक्रमों को बाधित करने, हमला करने, छात्रों को मारने–पीटने का लाइसेंस एबीवीपी को प्रशासन, पुलिस और सरकार की तरफ से मिला हुआ है। फरवरी 2017 में रामजस कॉलेज में 'प्रतिरोध की संस्कृति' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम पर इनलोगों ने मीडिया और पुलिस के सामने पथराव किया। छात्रों और प्रोफेसरों को भी पीटा गया।

• शिक्षा के निजीकरण के एजेण्डे पर चलते हुए वहां के 7 कॉलेजों को 'वित्तीय स्वायत्तता' देने की घोषणा की गई है। अब सेंट स्टीफेन, हिंदू कॉलेज, हंसराज, श्रीराम कॉजेल ऑफ कॉमर्स, पीजीडीएवी, वेंकटेश्वर कॉलेज जैसे डीयू के बेहतरीन कॉलेजों को कहा जा रहा है कि 'कॉलेज चलाने के लिए पैसा छात्रों से निकालो!'। यह पहले से ही बढ़ चुकी फीस को और भी बढ़ाने की ओर उठाया गया कदम है।

आज सरकार अपने पिट्ठू छात्र-संगठन के साथ मिलकर डीयू के बचे-खुचे लोकतांत्रिक वातावरण को भी नष्ट कर देने पर आमादा है। दूसरी ओर, प्रशासन वहां की शिक्षा को बाजार के हवाले करने पर आमादा है। सार्वजनिक शिक्षा के इस सबसे बड़े संस्थान को बचाने की लड़ाई इसी पीढ़ी को लड़नी है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयः कैंपस लोकतंत्र, महिलाओं व वंचितों के अधिकारों पर आरएसएस द्वारा स्थगन

एक विश्वविद्यालय में किस तरह से कैंपस लोकतंत्र, बराबरी के अधिकार और असहमति की आवाज़ों को ख़ामोश कर दिया जाता है, इसका बड़ा उदाहरण बीएचयू है। मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही वहां वाइस चांसलर के रूप में गिरीश चंद्र त्रिपाठी को नियुक्त कर दिया। इनका मानना है कि 'सरकार आरएसएस की है तो बीएचयू भी तो उनका ही होगा'। वहां सिर्फ संघ की शाखायें लगाई जा रही हैं बात इतनी भर नहीं है, बल्कि पूरा कैम्पस ही संघ के रंग में रंगने की कोशिशें जारी हैं-

• मई 2016 में बीएचयू लाइब्रेरी का समय पहले की तरह 24 घंटे करने की मांग उठी, जिसमें 9 छात्रों को 2 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। इन छात्रों के निलंबन का आधार 'कैम्पस में धरना देना' बताया गया। निलंबन के बाद भी जब छात्र कैम्पस के सवालों को उठाते रहे तो प्रशासन ने उन्हें 307 जैसी गंभीर आपराधिक धाराओं में फंसाने की कोशिश की। एक साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है जिसमें कोर्ट ने निलंबन और आपराधिक धाराओं को हटाते हुए सभी परीक्षाओं को पुनः आयोजित कराने का आदेश दिया।

• पिछले दिनों बीएचयू में 'लैंगिक असमानता' का मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया से लेकर संसद तक चर्चा का विषय रहा। भाजपा एक ओर 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' का नारा देकर अपनी पीठ ठोक रही है वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू की छात्राएं अपने बुनियादी अधिकारों से भी वंचित कर दी गई हैं –

- कैम्पस में स्थित महिला महाविद्यालय (MMV) की छात्राओं और उनके अभिभावकों से नामांकन के दौरान ही किसी विरोध-प्रदर्शन या धरना में शामिल न होने का अंडरटेकिंग ले लिया जाता है।
- डिजिटल इंडिया के इस दौर मे गर्ल्स हॉस्टलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई है। इससे उन्हें छात्राओं के 'बहक जाने' की चिंता है।
- कला व सामाजिक विज्ञान (स्नातक) में छात्राओं को मुख्य संकाय में दाखिला नहीं मिलता तथा छात्रों की अपेक्षा छात्राओं के पास 'सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन' के बहुत कम विकल्प मौजूद होते हैं।
- यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कैम्पस में सुरक्षा कारणों से किसी छात्रा के साथ सुविधाओं तथा हॉस्टल के समय में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

लेकिन बीएचयू में संघ का गाइडलाइन चलता है। यहां 8 बजे के बाद इन्हें हॉस्टलों में कैद कर दिया जाता है। रात 10 बजे के बाद फोन से बात करने तथा अपने ही कम्पाउंड में एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जाने पर पाबंदी है।

- लड़कियों के हॉस्टल के मेस में नॉन-वेज खाना नहीं दिया जाता।
- रात में 10 बजे के बाद भी पढ़ने की इच्छा रखने वाली लड़कियां, वीसी के अनुसार 'अनैतिक' हैं।

• हाल ही में संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार दलित उत्पीड़न की घटनाओं मे बीएचयू पहले नंबर पर है। बीएचयू में निर्णय लेने वाली सभी 'बॉडी' (जैसे ऐकेडमिक काउंसिल, एक्ज़ेक्यूटिव काउंसिल) में सामाजिक विविधता को दरकिनार कर एक जाति विशेष का वर्चस्व कायम है।

• हाल ही में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बीएचयू की सारी नियुक्तियों पर रोक लगा दिया क्योंकि उनमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। सामान्य की तय सीटों से अधिक नियुक्तियां की जा रही हैं जबकि आरक्षित सीटों पर 'नॉन फाउंड सूटेबल' लगाकर खाली छोड दिया जाता है।

• बीएचयू को आरएसएस की कार्यशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। कैम्पस में एक ओर जहां राजनीतिक परिचर्चाओं से लेकर अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों पर प्रतिबंध है वहीं दूसरी तरफ आरएसएस-एबीवीपी के नेताओं के कार्यक्रम, शाखाएं और बड़ी संख्या में लाठी भांजती हुई रैली खुलेआम प्रशासनिक संरक्षण में हो रहे हैं।

• बीएचयू लाइब्रेरी को 24X7 करने, कैम्पस में अभिव्यक्ति व वाद-विवाद की संस्कृति स्थापित करने, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।

इलाहाबाद विश्वविद्यालयः कैंपस लोकतंत्र और उच्च शिक्षा के अधिकारों से छात्रों की बेदख़ली

इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय इन दिनों भाजपा सरकार के लिए कैंपसों पर हमले की एक नई प्रयोगशाला है।

• 20 नवंबर, 2015 को भाजपा के धुर सांप्रदायिक नेता योगी आदित्यनाथ को छात्रसंघ कार्यालय के 'उद्घाटन' के लिए आमंत्रित किया गया। छात्रसंघ अध्यक्षा ने अन्य प्रगतिशील छात्र-संगठनों के साथ मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया। प्रशासन के इशारे पर इस दौरान एबीवीपी ने आम छात्रों के साथ मारपीट की तथा आदित्यनाथ का विरोध करने वाले छात्र-नेताओं को निशाना बनाया गया।

• इस वर्ष वहां प्रशासन ने छात्रों से जबरन 'हॉस्टल वॉशआउट' कराया तथा मौका देखकर कई छात्र-विरोधी नीतियों को लागू करने पर उतारू हो गया।

200% से भी अधिक की फीस-वृद्धि का फैसला लिया गया, जिसे छात्रों के विरोध के बाद हालांकि वापस लिया गया।

- इस वर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन फॉर्म भरने की फीस भी बढ़ा दी गई है। पत्रकारिता जैसे कोर्स में फार्म भरने के लिए पहले जहां 600 रुपये लगते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।
- इस सरकार के साथ संकट यह है कि यह शिक्षा में जैसे ही गुणवत्ता कहती है, उसका अर्थ होता है- आम छात्रों को शिक्षा से बेदखल कर देना। इलाहाबाद विवि में छात्रों की एक बड़ी संख्या को विश्वविद्यालय में आने से रोकने के लिए न्यूनतम अंको की बाध्यता लगायी गई। इस बाध्यता का मकसद अप्रत्यक्ष तरीके से सीट कटौती करना था. छात्रों के आंदोलन के बाद प्रशासन को अपने इस फैसले से आंशिक रूप से पीछे हटना पड़ा।
- पिछले वर्ष आन्दोलन कर के छात्रों ने कई कॉलेजों जैसे सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, जगत तारन डिग्री कॉलेज आदि में परास्नातक के कोर्स चालू करवाए थे। लेकिन अलग-अलग नियमों के जरिए सीटें खाली रखकर विश्वविद्यालय उन संघटक कॉलेजों में इन कोर्सों को फिर से बन्द करने का तर्क निकाल रहा है।
- विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार का उच्च शिक्षा और शोध को लेकर कितना अगंभीर रवैया है, इसे देखिये। इस बार के शोध में प्रवेश लेने के लिए हिंदी, इतिहास (प्राचीन, मधयकालीन और आधुनिक), एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, अरबी, फारसी आदि विषयों में प्रवेश के लिए शोध की कोई भी सीट नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से ठीक पहले हिंदी के एक प्रोफेसर के फेसबुक वाल से छात्रों को पता चला कि विभाग में शोध की तेरह सीटें खाली हैं। अन्य कई विभागों में कई अध्यापकों से बात करने पर पता चला कि उनके

गाइडेंस में मात्र 2-3 छात्र शोध कर रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले दिनों एक अध्यापक के गाइडेंस में 8-10 छात्रों को शोध कराये जाने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपा चुका है। इसी तरह अरबी और फारसी की 2-2 सीटों को बाद में केवल फारसी की 2 सीट में बदल दिया गया।

- विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 80-90% छात्रों को दाखिला लेने की बाद किराये के कमरों की तलाश में यहाँ-वहाँ भटकना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है।
- तक़रीबन 525 शैक्षणिक पद खाली हैं। जिसे भरना है, ऐसी मंशा न तो सरकार की है न ही विवि प्रशासन की। (9 मार्च, 2017, 'हिन्दुस्तान टाइम्स')
- इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय को 24 घंटा खोलने की मांग लम्बे समय से उठाई जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसको सुनने को तैयार नहीं है। पिछले साल लम्बे आन्दोलन के बाद केन्द्रीय पुस्तकालय से स्नातक के छात्रों को किताबें मिलनी शुरू हुईं, लेकिन अभी भी किताबें केवल कला संकाय के छात्रों को ही मिल रही हैं। विज्ञान, वाणिज्य, विधि संकाय के छात्रों को यह सुविधा नहीं मिल रही है।
- विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए वॉशरूम की व्यवस्था को लेकर भी छात्रों को आन्दोलन करना पड़ता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखित आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक इस मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं की है।

इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विवि का दर्जा देकर भी सरकारों ने उसमें न तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की ओर ध्यान दिया और न ही सुविधाओं को बेहतर बनाने की ओर। मोदी सरकार अपने हमलों से इस विश्वविद्यालय की सुविधाओं में और भी कटौती करना चाहती है।

लखनऊ विश्वविद्यालयः संघ के एजेण्डे पर बदतर होती स्थितियां

- किसी तरह के लोकतांत्रिक-वैचारिक गोष्ठियों पर रोक लगाने वाला कुलपति डॉ. एसपी सिंह सावरकर विचार मंच की संगोष्ठी में 'सावरकर के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा' पर भाषण देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि लखनऊ विवि में 'सावरकर शोध पीठ' की स्थापना की जाएगी।

- पीएच.डी में लेने के लिए नियम तक बदल दिए। पहले इसमें जेआरएफ वाले छात्रों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था तथा नेट और नॉन-नेट वाले छात्रों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों देना पड़ता था। इसमें नेट वाले छात्रों को वरीयता दी जाती थी। इस बार प्रशासन ने अपने चहेते लोगों का

'चयन' करने के लिए इस नियम को हटा दिया। अब वहां सभी को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार देना होगा। नेट-जेआरएफ की वरीयता समाप्त कर दी गई है।

- अपने अधिकारों और मांगों के साथ आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ प्रशासन की शह पर एबीवीपी के गुण्डों से मारपीट करवाया जाता है।

- हॉस्टल, मेस, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर कोई ध्यान न तो सरकार का है न ही विश्वविद्यालय प्रशासन का।

पंजाब यूनिवर्सिटी: सरकार और प्रशासन के हमलों के समक्ष छात्र प्रतिरोध की नई उंचाई

हाल में पंजाब यूनिवर्सिटी सरकार की सीट कटौती और फीस-वृद्धि जैसे नीतिगत हमलों के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हुयी। यह विश्वविद्यालय 60% केन्द्र सरकार तथा 40% राज्य सरकार के पैसे से चलता है। भाजपा सरकार ने शिक्षा और कैम्पसों पर हमले के दौरान इस विश्वविद्यालय पर पूरी ताकत के साथ हमला किया। एक तरफ सीट भारी सीट-कटौती तो दूसरी ओर 1100% की फीस बढ़ोतरी। एक ओर कैंपस लोकतंत्र का स्थगन तो दूसरी ओर भाजपा-संघ की भगवाकरण की नीतियों को जबरन थोपना। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस चौतरफा हमले के खिलाफ निर्णायक लड़ाइयां लड़ीं-

- फीस-वृद्धि का आलम देखिये- बी.फार्मा कोर्स की फीस 5,080 रु से बढ़ाकर 50,000; एम.ए (पत्रकारिता) की फीस को 5,290 से बढ़ाकर 30,000; जबकि डेन्टल कोर्स में यह 86,400 से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दिया गया है। जिस कोर्स की फीस 7,000 थी, उसे 90,000 किया गया तथा 9,000 को 1 लाख कर दिया गया है। यह लगभग 1100% तक की फीस बढ़ोतरी है। यह सीधे-सीधे आम गरीब छात्रों को शिक्षा से बाहर धकेलने की सरकारी घोषणा है।

- इसके विरोध में 11 अप्रैल को छात्रों के प्रदर्शन पर चंडीगढ़ पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। 58 छात्रों को जेल में डाला गया। भाजपा सरकार छात्रों में भय और आतंक पैदा कर हर तरह के विरोध की आवाज को दबा देना चाहती है।

- इस फीस-वृद्धि का विरोध करने पर 66 छात्रों पर शुरूआत में 'देशद्रोह' का मुकदमा भी दायर कर दिया गया। आंदोलनकारी छात्रों को भाजपा-एबीवीपी लगातार 'देशद्रोही' और 'नक्सली' कहकर उनपर हमला करते रहे। भाजपा सरकार 'देश' की यह कौन-सी परिभाषा गढ़ना चाहती है जहां छात्र स्वयं को शिक्षा से बेदखल किए जाने के खिलाफ भी नहीं बोल सकते।

- इस आंदोलन की एकजुटता को तोड़ने के लिए प्रशासन ने घोषणा की कि यह फीस-वृद्धि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस पर लागू होगी, कॉलेजों पर नहीं। इसके बावजूद भी विभिन्न कॉलेजों के छात्र आंदोलन में डटे रहे।
- एक तरफ भाजपा की सरकार छात्रों को शिक्षा से बेदखल कर रही है तो दूसरी ओर उनका छात्र-संगठन एबीवीपी आंदोलन को गुमराह करने में लगा रहा। उनकी दिखावटी भूख-हड़ताल में भाजपा चंडीगढ़ के अध्यक्ष संजय टंडन पहुंचे और ये कहकर चले गए की 'फीस बढ़ोतरी तो जायज है तुमलोग क्यों बैठे हो।' उस दिन एबीवीपी अध्यक्ष कृष्ण शेरोन ने मीडिया में अपना बयान दिया कि हम फीस-वृद्धि के खिलाफ नहीं, बल्कि वीसी के इस्तीफे के लिए बैठे हैं।
- छात्र आंदोलन के दवाब में पीयू प्रशासन को इमरजेंसी सीनेट कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ी जिसमे छात्रों पर लादे गये फर्जी केस और फीस बढ़ोतरी का मुद्दा था। 7 मई को सीनेट की मीटिंग रखी गयी जिसका छात्रों ने घेराव कर दिया। छात्र सुबह 9 वजे से रात 8 बजे तक वहीं जम कर बैठे रहे। छात्रों के इस अटूट विश्वास और आक्रोश को देखते हुए सीनेट कमेटी को झुकना पड़ा। उन्हें फीस बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ी साथ ही छात्रों पर हुए सभी केस खारिज करने पड़े।

फीस बढ़ोतरी के विरोध में सड़क पर उतरे पीयू स्टूडेंट्स, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Publish Date:Thu, 06 Apr 2017 08:23 PM (IST) | Updated Date:Fri, 07 Apr 2017 04:00 AM (IST)

HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES

Clash between the protesting students and police during All Party protest for Fee hike outside VC office Panjab University on April 11, 2017 in Chandigarh, India.

सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों और प्रशासन की तानाशाही रवैये के खिलाफ पीयू का यह आंदोलन छात्र-आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर है, जो समस्त भारत के आंदोलनकारी छात्रों, न्याय और बराबरी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को एक नयी ऊर्जा देगा।

बिहार- पूरी शिक्षा प्रणाली निजी शिक्षा माफियाओं, कोचिंग संस्थानों, सेटिंगबाजों और भ्रष्टाचार के हवाले!

सामाजिक न्याय के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा-नीति के मामले में केंद्र की मोदी सरकार के रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मूलभूत आवश्यकताओं की ओर से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में मोदी और नीतीश एक जैसे हैं। शिक्षा में हो रहे निजीकरण तथा रोजगार के अवसरों में लगातार हो रही कटौती की वजह से शिक्षा-रोजगार के क्षेत्र में घोटाले आम बात हो गयी है। बिहार की शिक्षा-व्यवस्था की दयनीय स्थिति को ठीक करने में वहां की सरकारों की कोई मंशा नहीं रही है-

- भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 64.8% की जगह बिहार की साक्षरता दर 47% है। भारत की महिला साक्षरता दर 53.7% के समानांतर बिहार की महिला साक्षरता दर 33.1% है। बिहार के किशनगंज जिले में केवल 18.49% महिलायें ही साक्षर हैं। (2001 की जनगणना से)
- प्रतिलाख छात्रों के लिए 26 कॉलेज के राष्ट्रीय दर की जगह बिहार में प्रति लाख छात्रों पर केवल 6 कॉलेज हैं।

• 2016 में हुए 'टॉपर्स घोटाले' ने बिहार के शिक्षण संस्थानों और राजकीय शिक्षा-विभाग में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। 2017 की इसी प्रकार BSSC की परीक्षा में पेपर लीक और उसके बाद सरकार द्वारा मंत्रियों-अफसरों को बचाने की कोशिश करना बिहार के भीतर संस्थागत भ्रष्टाचार को उजागर करता है।

• 2017 में वैशाली के अम्बेडकर बालिका विद्यालय में 10वीं कक्षा की दलित छात्रा डीका कुमारी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या ने बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में दलितों और महिलाओं की वास्तविक स्थिति को सामने ला दिया। प्रशासन और पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की शर्मनाक कोशिश की। आइसा और ऐपवा के सतत आंदोलनों और दबाव के कारण इस मामले में एफआईआर हो सका।

• पटना विश्वविद्यालय के 'आर्ट्स एंड क्राफ़्ट कॉलेज' में महिला विरोधी और जातिसूचक गाली देने वाले प्राचार्य के खिलाफ चले छात्रों के आंदोलन पर जिस तरीके से दमन किया गया और छात्रों को जेल भेजा गया ये सरकार के सामाजिक न्याय के ढोंग को सामने लाता है।

बिहार के ढहते विश्वविद्यालयों को केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियां और भी बर्बाद कर रही हैं-

पटना विश्वविद्यालयः
क्रमशः बर्बाद होता संस्थान

- पटना विवि में 70 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।
- छात्र पुराने घिसे-पिटे सिलेबस से पढ़ने के लिए अभिशप्त हैं।
- रोजगार-परक शिक्षा के नाम पर छात्रों से पैसा उगाही के लिए 'वोकेशनल कोर्स' की भरमार है। इन विषयों का न ही अपना विभाग है और न ही बेहतर शिक्षक। प्लेसमेंट सेल की बात करना तो मजाक करने जैसा है।
- छात्रावासों की भारी कमी है और जो हैं भी उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
- 2012 के बाद से पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव लंबित है।
- लाइब्रेरी की स्थिति दयनीय है और रेनोवेशन के नाम पर पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय को लंबे समय से बन जाने के बाद भी बंद कर के रख जा रहा है।
- केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह एमफिल/पीएचडी की सीटों में भारी कटौती की ठीक उसी तर्ज पर बिहार सरकार भी उच्च शिक्षा को समाप्त कर देना चाहती है। पटना विश्वविद्यालय ने पिछले चार सालों से पीएचडी में नामांकन के लिए पी.आर.टी टेस्ट नहीं लिया है।

मगध, मिथिला, वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, बी.एन. मंडल, तिलका मांझी एवं बिहार विश्वविद्यालयः सबकी एक कहानी

- अनियमित सत्र और परीक्षाओं में गड़बड़ी यहां के लिए आम बात है। जयप्रकाश नारायण विवि में तो 2014, 2015 और 2016 तीनों वर्ष के पार्ट-1 की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है।
- सारे ही विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और कर्मचारियों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं। जेपी विवि में शिक्षकों और कर्मचारियों के तो 75-80% सीट खाली हैं। इसके बाबा हरिओम कॉलेज, मैरवा में सिर्फ एक शिक्षक हैं।
- अधिकांश कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ परीक्षा-संबंधी औपचारिकताएं होती हैं।

• छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह से प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है।

• छात्रों के लिए छात्रावास की घोर कमी है। कुछेक छात्रावास हैं भी तो बेहद दयनीय हालत में। चार जिलों (मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय) में 44 कॉलेजों वाले ललित नारायण मिथिला विवि में 100 छात्रों के रहने लायक केवल एक छात्रावास है।

• पीजी (मास्टर्स) की पढ़ाई व विषयों की विविधता का घोर अभाव है। बीन.एन. मंडल विवि 7 जिले में फैला हुआ है लेकिन सिर्फ 4 जिलों के 4 कॉलेजों में ही पीजी की पढ़ाई होती है। उसमें भी सिर्फ एक कॉलेज में इतिहास–विभाग है।

• पुस्तकालय, रीडिंग रूम, प्रयोगशाला जैसी मूलभूत सुविधायें भी छात्रों को नहीं है।

जादवपुर यूनिवर्सिटी:
संघ और निजीकरण का हमला एवं छात्र-आंदोलन

जादवपुर यूनिवर्सिटी अपने कैंपस लोकतंत्र और वाद-विवाद की संस्कृति के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों इस संस्थान पर भी हमले हुए हैं। सरकार इस महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान को कमजोर करने की कोशिश बार-बार करती है-

- संघ, भाजपा और उनके इशारों पर काम करने वालों ने जादवपुर कैंपस को बदनाम करने का अभियान ले रखा है।
- इस वर्ष वहां के छात्रों को मिलने वाला नॉन-नेट फेलोशिप को बंद कर दिया गया है।
- अंतर-अनुशासनिक विभागों और विषयों में इस वर्ष एमफिल/पीएचडी में नामांकन के लिए सीटें नहीं निकाली गई हैं।

जनसंचार (मास कॉम्युनिकेशन) में मास्टर्स (एमए) का कोर्स वहां हाल में शुरू किया गया। इसकी फीस 30,000 रुपये सलाना है जोकि बाकी कोर्स की फीस का 30 गुना है।

महाराष्ट्र:
शिक्षा को निजीकरण की ओर धकेलने के नये प्रयास

- पहले से ही मुंबई विश्वविद्यालय के अधीन करीब 80,000 सीटें (करीब एक तिहाई) सेल्फ फाइनांस के दायरे में हैं। (टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 मई 2015)
- महाराष्ट्र विधानसभा में 22 मार्च 2017 को एक बिल पास कर पुणे में प्राइवेट 'सेल्फ फाइनांस यूनिवर्सिटी' खोलने की मंजूरी दी गई। (एनडीटीवी, 22 मार्च 2017)
- इसी के साथ-साथ वहां की विधानसभा जल्दी ही और पांच प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी देने वाली है। (हिंदुस्तान टाइम्स, 1 अप्रैल 2017)
- महाराष्ट्र की भाजपा सरकार आदिवासी छात्रों की हितैषी होने का दिखावा तो करती है, लेकिन नीतियां बनाकर उनके अधिकारों पर हमला करने से बाज

Hindustan Times 1/4/17
Maha likely to get five private universities offering unique courses
State education minister Vinod Tawde said that the approvals for the five universities were pending since the tenure of the government.
NDTV 22/3/17
Maharashtra Legislative Assembly Passes Bill To Set Up Self Financing University In Pune
Education | Press Trust of India | Updated: March 22, 2017 14:58 IST
Times of India 24/5/15
Now, self-financed courses make up a 3rd of degree seats
Yogita Raol TNN | May 24, 2015, 05.00 AM IST
A- A+

नहीं आती। वहां आदिवासी छात्रों के लिए अबतक जो छात्रावास थे, उनकी संख्या काफी कम है, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, यहां तक कि कई छात्रावास तो किराये के मकान में चल रहे हैं। सरकार 'दीनदयाल उपाध्याय स्कीम' के नाम पर इन छात्रावासों को बंद कर छात्रों को कुछ पैसे थमा देने की कोशिश कर रही है।

टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस: फंड-कट, सीसीटीवी और आधारकार्ड की प्रशासनिक मंशा

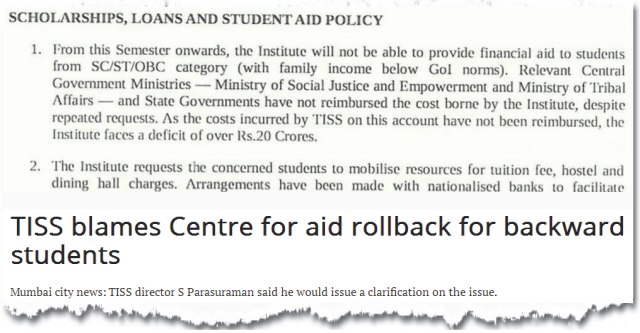

SCHOLARSHIPS, LOANS AND STUDENT AID POLICY

1. From this Semester onwards, the Institute will not be able to provide financial aid to students from SC/ST/OBC category (with family income below GoI norms). Relevant Central Government Ministries — Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs — and State Governments have not reimbursed the cost borne by the Institute, despite repeated requests. As the costs incurred by TISS on this account have not been reimbursed, the Institute faces a deficit of over Rs.20 Crores.

2. The Institute requests the concerned students to mobilise resources for tuition fee, hostel and dining hall charges. Arrangements have been made with nationalised banks to facilitate

TISS blames Centre for aid rollback for backward students

Mumbai city news: TISS director S Parasuraman said he would issue a clarification on the issue.

इस संस्थान में प्रशासन ने मोदी सरकार की शिक्षा नीति का अनुकरण करते हुए तकरीबन दो-गुना तक फीस-वृद्धि कर दी। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को महंगी फीस भरने में संस्थान से मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी बंद कर दिया गया है। यही नहीं वहां के कैंपस लोकतंत्र को स्थगित करने का भी एक एजेण्डा है। सभी छात्रों के लिए आधार-कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य बनाया जा रहा है, उपस्थिति जांच के लिए प्रशासन बायोमेट्रिक्स मशीन लगाने पर तुला हुआ है, कैंपस में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो रही है। छात्रों ने शुरूआत से ही इन हमलों-प्रस्तावों का विरोध किया, लेकिन सरकार और टीआईएसएस प्रशासन अपनी ही धुन में है।

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी: वीसी अप्पाराव और सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, कैंपस लोकतंत्र और वाद-संवाद की संस्कृति पर हमला और तेज

देश के केंद्रीय मंत्रियों (स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय) के इशारे पर शोध-छात्र रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या करने वाले वीसी अप्पाराव आज भी इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। संघ-भाजपा सरकार के इशारे पर इन्होंने कैंपस-लोकतंत्र, छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार और वाद-विवाद की संस्कृति पर हमले को और भी तेज कर दिया है-

- अभी हाल ही में छात्रों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने छात्रों से बिना संवाद किए छात्रसंघ के लिए एक नए छात्रविरोधी संविधान का प्रारूप ला दिया है, जिसे वह 15 अगस्त को लागू करने वाला है। इस नये 'संविधान' के मुताबिक छात्रसंघ का सर्वेसर्वा स्वयं वाइस चांसलर होगा। विडंबना देखिये कि जिस छात्रसंघ को प्रशासन और वीसी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए ही चुना जाता है, उसका सर्वेसर्वा स्वयं वीसी होना चाहता है।
- अभी 23 मार्च के आस-पास प्रशासन ने प्रशासन भवन और अकादमिक भवन के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट करने पर रोक लगा दिया है।
- प्रशासन जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर छात्रों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है।
- एचसीयू को जेल बना देने की साजिश की जा रही है। राजनैतिक-वैचारिक विषयों पर सामान्य 'पब्लिक मीटिंग' तक नहीं होने दिया जा रहा है। बाहर से किसी स्पीकर को बुला पाना और कार्यक्रम की 'अनुमति' मिलना मुश्किल हो गया है। ❑

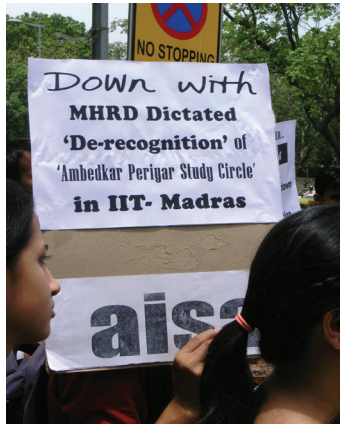

OPPRESSION IS YOUR
PRIVILEGE
PROTEST IS OUR RIGHT !!
बराबरी का हक़
बराबरी का दावा
नहीं तो मुठभेड़
और धावा...
AISA

मैं घास हूँ
मैं आपके हर किए-धरे पर उग आऊँगा

बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर
बना दो होस्टल को मलबे का ढेर
सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर

मेरा क्या करोगे
मैं तो घास हूँ हर चीज पर उग आऊँगा

– पाश

सहयोग मूल्य: रु. 20